



04 - महिला आरक्षण बिल
नहीं, परिसीमन
विधेयक गिरा है



05 - चुनाव में पार्टी और
निष्पक्ष पुनरीक्षण जरूरी

A Daily News Magazine

मोपाल
सोमवार, 27 अप्रैल, 2026



मोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 234, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - डिजिटल युग के ना
दौर में जनसंपर्क की
भूमिका और अधिक...



07 - रेशन पर यात्रियों को
स्वच्छ और ठंडे जल की
सेवा दी

कुरुक्षेत्र

प्रसंगवश

आखिर कैसे सुलझेगी परिसीमन की गुत्थी?

यूसुफ अंसारी
भारतीय लोकतंत्र में परिसीमन की गुत्थी लंबे समय से उलझी हुई है। यह संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों तथा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का जनसंख्या के अनुरूप पुनर्निर्धारण है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें फ्रीज होने के बाद से उत्तर भारत में तेज जनसंख्या वृद्धि और दक्षिण के राज्यों में परिवार नियोजन की सफलता के कारण प्रतिनिधित्व में असंतुलन बढ़ गया। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को तीन विधेयक-संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, संघ क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक-लोकसभा में पेश किए। इनका मकसद लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना, 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन और महिला आरक्षण को 2029 चुनाव से पहले लागू करना था। लेकिन 17 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत (352 वोट) हासिल नहीं कर सका। विधेयक के पक्ष में 298 और 230 विरोध में पड़े। सरकार ने परिसीमन विधेयक वापस ले लिया। इससे राजनीतिक विवाद और गहरा गया है।

संघीय संतुलन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि लोकसभा में राज्यों की ताकत केंद्रीय नीतियों, वित्त आयोग के फंड बंटवारे और संसदीय बहस को प्रभावित करती है। बिना परिसीमन के लोकतंत्र अधूरा है। 2023 के महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए भी परिसीमन अनिवार्य है, क्योंकि नए क्षेत्रों में 33% महिला आरक्षण रोटेशन से लागू होगा। सरकार का तर्क है कि इससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बनेगा। लोकसभा सीटों का कोटा संविधान के अनुच्छेद 81 पर आधारित है। 1976 में 42वें संशोधन और 2001 में 84वें संशोधन ने इसे 1971 जनगणना पर फ्रीज कर दिया, जो 2026 तक प्रभावी था। परिसीमन आयोग कुल जनसंख्या को कुल सीटों से विभाजित कर औसत निर्वाचन क्षेत्र का आकार तय करता है। फिर प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को इस औसत से विभाजित कर सीटें तय की जाती हैं। 1971 में औसत प्रति सीट जनसंख्या करीब 10 लाख थी। 2011 जनगणना पर अगर शुद्ध अनुपात लागू होता, तो उत्तर भारत को भारी फायदा और दक्षिण को नुकसान होता। प्रस्तावित विधेयकों में संसद को किसी भी जनगणना (2011 सहित) को आधार बनाने का अधिकार देने का प्रावधान था, जिससे लचीलापन आता। गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि सभी राज्यों की सीटें करीब 50% बढ़ाई जाएंगी, ताकि अनुपात बरकरार रहे। लेकिन विधेयक पास नहीं होने से यह कोटा अभी 1971 फॉर्मूले पर अटक रहा।

2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। अगर शुद्ध जनसंख्या अनुपात पर सीटें बांटी जाएं (बिना अतिरिक्त वृद्धि के), तो उत्तर भारत को भारी फायदा होगा। दक्षिण के राज्यों (129 सीटें) का हिस्सा कुल में 24% से घटकर 20% के नीचे आ जाता। लेकिन सरकार ने 50% समान वृद्धि का फॉर्मूला सुझाया था, जिसमें सभी राज्यों की सीटें करीब 50% बढ़तीं और अनुपात बरकरार रहता। दक्षिणी राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जातीं (शेयर 23.8% से 23.9%)। तमिलनाडु 39 से 59, केरल 20 से 30, कर्नाटक 28 से 42, आंध्र प्रदेश 25 से 37, महाराष्ट्र 48 से 72, उत्तर प्रदेश 80 से 120 के आसपास। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि कोई राज्य नुकसान में नहीं जाएगा। PRS इंडिया और अन्य विश्लेषणों के अनुसार, अगर कुल सीटें 850 रखी जातीं, तो यह सर्वमान्य समाधान होता। लेकिन इस पर सरकार विपक्ष को विश्वास में नहीं ले पाई। विधेयक पास न होने से ये आंकड़े अभी सैद्धांतिक ही रह गए। शुद्ध 2011 आधार पर दक्षिण की चिंता जायज थी, जबकि सरकार का फॉर्मूला संतुलन बनाता।

16 अप्रैल 2026 के विधेयकों के अनुसार हां, संभव था। वर्तमान कानून में 2026 के बाद पहली जनगणना (2027) के आधार पर परिसीमन होता, जो 2029 चुनाव से पहले मुश्किल था। लेकिन संविधान संशोधन से 2011 जनगणना को आधार बनाने का रास्ता खुलता। परिसीमन आयोग (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का अध्यक्षता में) 1-2 साल में काम पूरा कर सकता था। सरकार का उद्देश्य महिला आरक्षण को 2029 से लागू करना था। लेकिन विधेयक के हारने और वापस लेने के बाद यह संभावना फिलहाल टल गई। अब 2026 के बाद की जनगणना (संभवतः 2027) पर परिसीमन होगा, जो 2034 चुनाव तक खिंच सकता है। दक्षिणी राज्यों ने विरोध किया कि 2011 आधार से उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। विपक्ष ने इसे 'उत्तर को पुरस्कार' बताया। इसलिए 2029 चुनाव अभी पुराने मानचित्र पर ही होने की संभावना है।

विंड एनर्जी में बहुत आगे बढ़ रहा भारत

● पीएम मोदी बोले- दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बना मन की बात में शांति के लिए दिया बुद्ध का संदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 133वें एपिसोड में देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों से लेकर वैश्विक मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दुनिया से भगवान बुद्ध के आदर्शों को अपनाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत विंड एनर्जी में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चुनावों की भागदौड़ के बीच, आपके संदेशों और पत्रों के जरिए हम नागरिकों की उपलब्धियों की खुशियां साझा करते रहे हैं। इस बार आइए 'मन की बात' की शुरुआत देश की ऐसी ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि से करें। कुछ दिन पहले भारत के परमाणु वैज्ञानिकों ने देश को एक और बड़ी उपलब्धि से गौरवान्वित किया है।



वैश्विक तनाव पर दिया बुद्ध का संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि कई का महीना एक शुभ अवसर के साथ शुरू हो रहा है और कुछ ही दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे। उन्होंने देशवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति की शुरुआत हमारे भीतर से होती है और स्वयं पर विजय सबसे बड़ी जीत होती है।

सऊदी के बाद अबू धाबी पहुंचे एनएसए

अबू धाबी (एजेंसी)। मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अबू धाबी पहुंचे हैं। शनिवार 25 अप्रैल को उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। बैठक का मुख्य जोर सुरक्षा चिंताओं, आर्थिक हितों के साथ ही इजरायल-ईरान युद्ध के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आपसी तालमेल पर था।

पवन ऊर्जा में भारत अब बड़ी शक्ति

पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि आज वह एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहते हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना जीवन एक पल भी संभव नहीं है- यह शक्ति है पवन ऊर्जा। उन्होंने कहा कि यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है और आज पवन ऊर्जा देश के विकास की नई कहानी लिख रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने हाल ही में इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और देश की पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है, जिससे भारत दुनिया के अग्रणी चार देशों में शामिल हो गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कोटा जिले में श्री कृष्ण यदुवंशी अहीर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुए शामिल मग्न और राजस्थान के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगी पार्वती-कालीसिंध-चम्बल परियोजना

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चंबल मैया का आशीर्वाद मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रांतों को मिल रहा है। हमारा प्रदेश अनेक नदियों के उद्गम के कारण नदियों का मायका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जोड़ीदार प्रदेश है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से स्वीकृत पार्वती- काली सिंध - चंबल अंतर्राज्यीय परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान लाभान्वित होंगे। पीकेसी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कोटा जिले में श्रीकृष्ण यदुवंशी अहीर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।



मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 16 संस्कारों में पाणिग्रहण संस्कार शामिल है। विवाह ही कुल और गोत्र को आगे बढ़ाते हुए अमरता देते हैं। विवाह से जीवन साथी के साथ बेटियों को नए माता-पिता मिलते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामूहिक विवाह समारोह में नव दंपतियों को आशीर्वाद और मंगलकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान में सामूहिक विवाह काफी उपयोगी हैं। मेरे अपने बेटे का विवाह सादगी पूर्वक किया था। परिवारों को खर्चिले विवाहों के कारण आर्थिक कष्ट उठाने होते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने समाज का मार्गदर्शन किया। धर्म मार्ग पर चलने की सभ्यता को प्रेरणा दी। अनेक कष्ट सहते हुए उनका जीवन एक उदाहरण बना। भगवान श्री कृष्ण ने लोकतंत्र की स्थापना का उदाहरण दिया था, जब कंस के वध के पश्चात स्वयं सत्ता नहीं सभलती। वे लोकतंत्र के सच्चे नायक थे। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। मध्य प्रदेश सरकार श्रीकृष्ण पाथेय का विकास कर रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह निश्चित ही प्रशंसनीय है कि यदुवंशी समाज वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। निःशुल्क विवाह समारोह का लाभ युवाओं को मिल रहा है। श्री बिरला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं जोड़ीदार प्रदेश : यादव

रक्षा कर रहे हैं। श्री बिरला ने कहा कि यह निश्चित ही प्रशंसनीय है कि यदुवंशी समाज वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। निःशुल्क विवाह समारोह का लाभ युवाओं को मिल रहा है। श्री बिरला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं जोड़ीदार प्रदेश : यादव

राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जैसे आयोजन समाज में व्याप्त गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने का कार्य करते हैं। राजस्थान के उर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आज समाज के युवा सेना में शामिल होकर सीमा की

मिलेगा। राजस्थान के विधायक महंत बाबा बालक नाथ ने कहा कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने यदुवंशी कुल में जन्म लेकर पूरे समाज को धन्य किया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में गरीब और पिछड़ा वर्ग के परिवारों को सामूहिक विवाह में शामिल कर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। यदुवंशी समाज धर्म के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ने वाला समाज है। सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से शारीरिक विवाह में फिजूल खर्ची रुकी है। कार्यक्रम में अनेक संत-वृद्ध, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

● एलएसी पर बढ़ेगी ताकत, चीन की नींद उड़ाएगी भारत-दक्षिण कोरिया की ये दोस्ती!

दक्षिण कोरियाई तकनीक से लैस होंगी अपनी तोपें

नई दिल्ली/सियोल (एजेंसी)। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बनने वाले सैन्य संबंध पर चीन की गहरी नजर है। खासकर भारत की दक्षिण कोरिया के साथ तोपखाने और एंटी-एयरक्राफ्ट गनों के क्षेत्र में रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने की कोशिश को चीन अपने लिए संवेदनशील मान रहा है। माना जा रहा है कि भारत इन तोपों को हिमालय में उन क्षेत्रों में तैनात करेगा जहां चीन से विवाद रहता है। भारत की तीन-दिवसीय यात्रा के दौरान सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के



बाद, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-युंग ने घोषणा की कि सियोल और दिल्ली अपने आर्थिक सहयोग को बेहतर बनाने पर सहमत हो गए हैं। इसके तहत जहाज निर्माण, रक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली ने कहा कि दक्षिण कोरिया भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति का पूरी तरह से समर्थन करता है और उसे उम्मीद है कि वह भारतीय रक्षा उपकरणों के उत्पादन और संचालन में सक्रिय रूप से मदद करेगा।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध पर चीन की टेढ़ी नजर

हंफुंग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर कांग जून-यंग ने कोरिया टाइम्स से कहा कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि बीजिंग, दक्षिण कोरिया और भारत के बीच रक्षा और स्पलाइंड-वेन सहयोग को बहुत ही आलोचनात्मक नजर से देखेगा। उन्होंने कहा खास तौर पर चीन भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है इसलिए बीजिंग इस बात को लेकर स्वाभाविक रूप से संवेदनशील है कि दक्षिण कोरिया के हथियार सिरस्टम से भारत की सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने आगे कहा चीन सिर्फ नियात से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान है।

भारत-दक्षिण कोरिया के-9 वज्र समझौते पर ड्रैगन की तीसरी आंख है सक्रिय

आपको बता दें कि के-9 वज्र-ए भारत में ही बनाया जाता है और यह दक्षिण कोरिया के के-9 थंडर डिजाइन पर आधारित है। इसका सिस्टम हानवा एयरोस्पेस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए तैयार किया गया था और इसे भारतीय सेना के रेगिस्तानी और ऊंचे पहाड़ी इलाकों के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है। भारतीय सेना ने इन हथियारों को देश के उत्तरी लद्दाख इलाके में तैनात किया है जिसका मकसद चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सीमा तनाव के बीच अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाना है। दिल्ली के विदेश मंत्रालय के परियोजना कुमानन ने सोमवार को ली की यात्रा के दौरान कहा कि भारत दक्षिण कोरिया के साथ अपने रक्षा उद्योग सहयोग को तीसरे चरण तक विस्तार देना चाहता है। सिंगापुर के एस. राजाचेल्लम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में साउथ एशिया प्रोग्राम के सीनियर एनालिस्ट निशांत राजीव ने कहा कि होवित्जर और एंटी-एयरक्राफ्ट गन भारत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि दक्षिण कोरिया से मिला के-9 आर्टिलरी सिस्टम भारत की विवादित सीमाओं पर उसकी मारक क्षमता को और बढ़ा देता है।

टेकऑफ के दौरान स्विस प्लेन का इंजन फेल, आग लगी

6 घायल, 4 नवजात समेत 232 लोग सवार थे, फ्लाइट ज्यूरीख जा रही थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली एयरपोर्ट में टेकऑफ के दौरान स्विस प्लेन का इंजन फेल हो गया। स्विस एयरलाइंस की एस 147 फ्लाइट शनिवार देर रात 1.08 बजे टेकऑफ करने वाली थी। तभी उसका एक इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान रोक दिया। अधिकारियों ने बताया कि रनवे पर इमरजेंसी स्ट्राइड का इस्तेमाल करके सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। 6 यात्री घायल हो गए। फ्लाइट स्विट्जरलैंड के ज्यूरीख जाने वाली थी। स्विस एयरलाइन ने एक बयान में कहा, हमें दिल्ली में फ्लाइट एस 147 से जुड़ी घटना के बारे में जानकारी मिली है। जिस विमान में खराबी आई, वह एयरबस एस 330 है। घटना भारतीय समय के अनुसार रात 1 बजे के बाद की है। जैसे ही विमान टेकऑफ करने के लिए रनवे में आया। विमान के बाईं ओर लैंडिंग गियर से धुआं निकलता देखा गया।



संक्षिप्त समाचार

एएपी सरकार ने भज्जी से सिक्थोरिटी छीनी

● पंजाब पुलिस हटाई, केंद्र ने घर पर सीआरपीएफ लगाई ● साहनी बोले- केजरीवाल ने मुझसे इस्तीफा मांगा

जालंधर (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने को लेकर मचा घमासान थम नहीं रहा है। पंजाब की एएपी सरकार ने पूर्व क्रिकेटर व पार्टी छोड़ने वाले राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भज्जी की जेड कैटेगरी सिक्थोरिटी हटा ली है। उनके जालंधर स्थित घर पर तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को तुरंत वापस बुला लिया गया है। इसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार ने भज्जी को सीआरपीएफ की सिक्थोरिटी दे दी। उनके घर के बाहर ये जवान तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि



भज्जी ने अभी एएपी छोड़ने या बीजेपी जॉइन करने को लेकर कुछ नहीं कहा लेकिन राघव चड्ढा ने उनके भी साथ में होने का दावा किया था। भज्जी से पहले एएपी सरकार ने राघव चड्ढा की भी जेड-4 सिक्थोरिटी वापस ली थी। इसके बाद उन्हें केंद्र की तरफ से यही सिक्थोरिटी मिल गई। इसी बीच एएपी छोड़ने वाले दूसरे राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी ने दावा किया कि सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा मांगा था।

बायपास पुल का सुधार कार्य 15 दिन में पूर्ण करें: उप मुख्यमंत्री

महानगर की तर्ज पर संतरेगी रीवा की यातायात व्यवस्था, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार होगा 'रोडमैप'

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नवीन सॉफ्टवेयर हाउस सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि बायपास मार्ग में पुल के सुधार का कार्य 15 दिन में अनिवार्य रूप से पूरा कराए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी से बायपास मार्ग पर स्थित पुल के मरम्मत कार्य की विस्तृत जानकारी ली और हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 दिनों के भीतर पुल के सुधार का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा कराए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि पुल से



आवागमन बाधित होने के कारण शहर के भीतरी मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिससे आमजन को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में वैवाहिक सीजन के कारण रात्रि में सड़कों पर बढ़ती चहल-पहल को देखते हुए उन्होंने बायपास रोड के चौड़ीकरण कार्य को भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए यातायात बाधित करने वाले तत्वों पर वैधानिक कार्यवाही करें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चालानों कार्यवाही जारी रखें। शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टोय कार्यायोजना लागू करें। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने शहर में ऑटो रिक्शा के लिए सुनियोजित पार्किंग स्थलों का चिह्नकन करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा एक तेजी से उभरता हुआ महानगर है, अतः यहाँ की व्यवस्थाएं आधुनिक और भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत होनी चाहिए। श्री शुक्ल ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को 'फील्ड' पर सक्रिय होने तथा वास्तविक समस्याओं का निरीक्षण कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सुगम और निर्बाध यातायात उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा संभाग मध्यप्रदेश का ऐसा पहला संभाग बनने जा रहा है, जहाँ रिंग रोड और बुनियादी ढांचे का कार्य रिकॉर्ड समय में पूरा होने जा रहा है।

एयरलिफ्ट कर ले गया इजरायल भारत ने जारी की थी एडवाइजरी

तेल अवीव (एजेंसी)। इरान के साथ युद्ध और तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारत से करीब 240 लोगों को एयरलिफ्ट कर इजरायल ले गया है। ये सभी बेनी मेनाशे समुदाय के लोग हैं और माना जाता है कि ये सभी सैकड़ों साल पहले हमला होने के बाद इजरायल छोड़कर भागे थे। इजरायल एशिया में तनाव के बीच इजरायल ऑपरेशन विंग्स ऑफ डीन चलाकर इन्हें ले जाया गया है। हालांकि बेनी

मेनाशे समुदाय के सदस्यों को पहले भी कई बार इजरायल ले जाया जा चुका है लेकिन यह पहली बार है कि पश्चिम एशिया में चले रहे क्षेत्रीय युद्ध के माहौल में इतनी बड़ी संख्या में उन्हें हवाई मार्ग से वहाँ पहुंचाया जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू इस ऑपरेशन विंग्स ऑफ डीन को मंजूरी दी थी जिसके तहत पूर्वोत्तर भारत से बेनी मेनाशे समुदाय के सदस्यों

को हवाई मार्ग से इजरायल पहुंचाया गया है। द ज्यूइश एजेंसी फॉर इजरायल ने बताया है कि गुरुवार (23 अप्रैल) को नई दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट में बेनी मेनाशे समुदाय के लोगों का पहला जत्था शामिल था। यह समुदाय मुख्य रूप से मणिपुर के चुराचंदपुर और मिजोरम-म्यांमार सीमा से सटे उन इलाकों में पाया जाता है जो कूकी-चिन-जो समुदायों के लिए जाने जाते हैं।



लड़ाई वाले इलाकों में बसाए जाएंगे भारत से गये यहूदी

जेएफआई की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि आज जो फ्लाइट उतरी उसमें दर्जनों युवा परिवार शामिल थे जो शुरू में नोफ हागलील में बने एजॉर्षन सेंटर में रहेंगे। उसके बाद वहाँ वे उन रिश्तेदारों से भी मिलेंगे जो पिछले सालों में आलिया (इसराइल में बसने) के लिए आए थे। जेएफआई ने आगे बताया कि ऐसे लोगों की कुल संख्या लगभग 600 होने की उम्मीद है। बाकी समुदाय के सदस्यों के आने वाले दिनों में रवाना होने की उम्मीद है। द जेरूसलेम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि नए आने वाले लोगों को हार्डफा के पास एक उपनगर किरयात याम में बसाया जाएगा। यह समूह आलिया और एकीकरण मंत्रालय और जेएफआई की अगुवाई वाली एक पहल के तहत बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचा। उम्मीद है कि उन्हें इसराइल के उत्तरी हिस्से में बसाया जाएगा जिसे हाल के महीनों में हिज्बुल्लाह ने निशाना बनाया है। वहीं द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि भारत ने इस एयरलिफ्ट में कोई मदद नहीं दी और भारत की जिम्मेदारी यह पक्का करना है कि विदेश यात्रा के दौरान हमारे नागरिकों की मानव-त्सकरी न हो। अधिकारी ने आगे कहा कि इसके अलावा हम किसी को भी कानूनी तरीके से बसाने से नहीं रोक सकते।



अगले महीने दस्तक देगा मानसून, होगी झमाझम बारिश

● मौसम एक्सपर्ट बोले- इस बार समय से पहले होगी बरसात

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण-पश्चिम मानसून इस बार 15 से 25 मई के बीच अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच सकता है। इसके बाद इसके 25 मई तक केरल पहुंचने के आसार हैं। मानसून को लेकर यह ताजा जानकारी यूरोपियन सेंटर फॉर मॉडियम रेंज वेदर फोरकास्टर्स (ईसीएमडब्ल्यूएफ) ने दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून के जल्दी आने की वजह इस बार अल नीनो है। अल नीनो की स्थितियां बनने की संभावना बहुत कम है। पॉजीटिव ओशन डाइपोल से भी बारिश के जल्दी होने और मानसून के पहले दस्तक देने की संभावना

है। यूरोपियन एजेंसी के मुताबिक मई के आखिर तक दक्षिण भारत में झमाझम बारिश हो सकती है। आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में तेज गर्मी और लू चलने का अलर्ट दिया है। उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आईएमडी के अनुसार इन दिनों कई राज्यों में अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के श्री गंगानगर में 44.5 डिग्री रहा। कई जगहों पर तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक अधिक रहा।

अब और नहीं सहेंगे कहने का समय आ गया है: मोदी

● पीएम ने कहा- टीएमसी का घमंड टूटा, भाजपा की जीत तय
● बोले- ममता की सरकार में मां-माटी और मानुष का सम्मान नहीं

कोलकाता (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बनगांव की रैली में कहा कि पहले फेज के मतदान में टीएमसी का घमंड टूट चुका है। दूसरे चरण में भाजपा की जीत तय होती

दिख रही है। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में छोटे-छोटे नेता और गुंडे खुद को सरकार समझने लगे हैं। पीएम ने कहा, '15 साल पहले टीएमसी 'मां, माटी, मानुष' का नारा देकर सत्ता में आई थी, आज वे इन शब्दों को बोल भी नहीं पाते। अगर ये लोग ये शब्द बोलेंगे, तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी के राज में मां-माटी और मानुष का सम्मान नहीं है। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। पीएम मनुआ समुदाय से जुड़े मंदिर भी जाएंगे। ये मंदिर संप्रदाय के संस्थापकों- हरि चंद और गुरु चंद ठाकुर का पवित्र स्थल है। रविवार को भाजपा सांसद रवि किशन ने हावड़ा में बीजेपी कैंडिडेट उमेश राय के समर्थन में रोड शो निकाला। इस दौरान कुछ टीएमसी समर्थक रोड शो में घुस गए। भाजपा समर्थकों से उनकी बहस भी हुई।



अत्याचार करने वाले गुंडों के साथ खड़ी है टीएमसी

पीएम ने कहा- बंगाल की महिलाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस बात से दिखती है कि हमने संदेशखाली पीड़िता और आरजी कर डॉक्टर की मां को चुनावी टिकट दिया है। टीएमसी की निर्मम सरकार बंगाल की महिलाओं पर अत्याचार करने वाले गुंडों के साथ खड़ी रहती है। अब समय आ गया है कि बंगाल की जनता कहे- अब और नहीं सहेंगे।

बंगाल में अब सिर्फ एक ही नारा है 'पलटानो दरकार'

पीएम ने कहा- 15 साल पहले हुगली नदी के आसपास का इलाका कभी मित्तों और फैक्ट्रियों का बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज वहां ताले लगे होने की खबरें आती हैं। ब्रिटिश दौर की फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं। पीएम ने कहा- आज सिर्फ एक ही फैक्ट्री और एक ही दुकान चल रही है-सिंडिकेट की कट-मनी और कमीशनखोरी की दुकान।

बंगाल में लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा

● आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर मड़के राहुल गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर कारा वार किया है। कांग्रेस सांसद ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर देवदीप की हत्या के आरोप

लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है। यहाँ नहीं राहुल गांधी ने राज्य सरकार से कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा देने की मांग भी उठाई है। राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी

की चुनाव बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों की ओर की गई हत्या बेहद निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना, मारना, मिताना, यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी, और न कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। यही

हमारी विरासत है, यही हमारा संकल्प। राहुल गांधी ने उठाई पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग- इसके साथ ही, राहुल गांधी ने जान गंवाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार को पूर्ण सुरक्षा के साथ ही मुआवजा देने की भी मांग उठाई। उन्होंने पोस्ट में लिखा- मेरी मांग स्पष्ट है- सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोरतम सजा मिले और देवदीप के परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मुआवजा मिले।



अमरीका में फायरिंग, ट्रंप को सुरक्षित निकाला

● 7 राउंड फायरिंग हुई, गेस्ट टेबल के नीचे छिपे

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉर्रस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। शनिवार शाम के इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत कई बड़े अफसर मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर फायरिंग की। ट्रंप और गेस्ट बॉलरूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को



पकड़ लिया गया है। पहले खबर आई थी कि हमलावर को मार गिराया गया। हमले के करीब डेढ़ घंटे बाद ट्रंप ने

आजादी के 78 साल बाद अबूझमाड में हुआ सबेरा

जहां कार्यक्रम, उसी होटल में ठहरा था हमलावर- पुलिस विभाग के अंतरिम चीफ जेफरी कैरोल के मुताबिक, हमलावर उसी होटल में मेहमान था, जहां व्हाइट हाउस कॉर्रस्पॉन्डेंट का डिनर कार्यक्रम हो रहा था। जिस कमरे में वह ठहरा था, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है।

रायपुर (एजेंसी)। उस रात हम सोए नहीं... बस टकटकी लगाकर देखते रहे कि बल्ब कैसे जल रहा है। इतापानार गांव के एक ग्रामीण के ये शब्द उस अहसास को बयां करते हैं जिसे हम और आप शापद कभी नहीं समझ पाएंगे। जिला मुख्यालय नारायणपुर से महज 30 किलोमीटर दूर, लेकिन दुर्गम रास्तों के कारण घंटों की दूरी पर बसा यह गांव अब तक सिर्फ स्मृतियों में था, नवशॉर पर नहीं। लेकिन अब यहां बिजली पहुंच चुकी है। किलोमीटर में नहीं, संघर्ष में मापा गया रास्ता- इतापानार तक बिजली पहुंचाना किसी रूटीन प्रोजेक्ट जैसा नहीं था। यहां रास्ता घने जंगलों, खड़ी पहाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ पगडंडियों से होकर गुजरता है।

अब बिहार के नए मंत्रिमंडल में दिखेगा सामाजिक समीकरण

● जेडीयू नए चेहरों को देगी मौका

पटना (एजेंसी)। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में क्षेत्रीय व सामाजिक समीकरण का नया स्वरूप दिख सकता है। अगड़ी, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति तीनों के संदर्भ में यह बात कही जा रही है। वहीं, जदयू अपने कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम पर यथास्थिति मोड़ में हैं। भाजपा कुछ पुराने चेहरों पर दृढ़ तो है ही, लेकिन क्षेत्रीय व सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख कई नए नाम को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। भाजपा में क्षेत्रीय समीकरण के मामले को सामाजिक समीकरण से जोड़ा जा रहा। मगध क्षेत्र से भाजपा ने अति पिछड़ी जाति को महत्वपूर्ण पद पर जगह दिया हुआ है। इसलिए यह कहा जा रहा कि मगध क्षेत्र से किसी सवर्ण जाति के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है।



हिज्बुल्ला जहां गिरा रहा बम वहीं बसाए जाएंगे भारतीय यहूदी

को हवाई मार्ग से इजरायल पहुंचाया गया है। द ज्यूइश एजेंसी फॉर इजरायल ने बताया है कि गुरुवार (23 अप्रैल) को नई दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट में बेनी मेनाशे समुदाय के लोगों का पहला जत्था शामिल था। यह समुदाय मुख्य रूप से मणिपुर के चुराचंदपुर और मिजोरम-म्यांमार सीमा से सटे उन इलाकों में पाया जाता है जो कूकी-चिन-जो समुदायों के लिए जाने जाते हैं।



लड़ाई वाले इलाकों में बसाए जाएंगे भारत से गये यहूदी

जेएफआई की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि आज जो फ्लाइट उतरी उसमें दर्जनों युवा परिवार शामिल थे जो शुरू में नोफ हागलील में बने एजॉर्षन सेंटर में रहेंगे। उसके बाद वहाँ वे उन रिश्तेदारों से भी मिलेंगे जो पिछले सालों में आलिया (इसराइल में बसने) के लिए आए थे। जेएफआई ने आगे बताया कि ऐसे लोगों की कुल संख्या लगभग 600 होने की उम्मीद है। बाकी समुदाय के सदस्यों के आने वाले दिनों में रवाना होने की उम्मीद है। द जेरूसलेम पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि नए आने वाले लोगों को हार्डफा के पास एक उपनगर किरयात याम में बसाया जाएगा। यह समूह आलिया और एकीकरण मंत्रालय और जेएफआई की अगुवाई वाली एक पहल के तहत बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचा। उम्मीद है कि उन्हें इसराइल के उत्तरी हिस्से में बसाया जाएगा जिसे हाल के महीनों में हिज्बुल्लाह ने निशाना बनाया है। वहीं द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि भारत ने इस एयरलिफ्ट में कोई मदद नहीं दी और भारत की जिम्मेदारी यह पक्का करना है कि विदेश यात्रा के दौरान हमारे नागरिकों की मानव-त्सकरी न हो। अधिकारी ने आगे कहा कि इसके अलावा हम किसी को भी कानूनी तरीके से बसाने से नहीं रोक सकते।

साइबर ठगी पर एमपी सरकार सख्त

5 आईपीएस समेत 8 अफसरों की टीम गठित, ठगों पर होगी त्वरित कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों से ठगी करने वालों पर अब सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। आम लोगों को लालच, डर और फर्जी योजनाओं के जाल में फंसाकर पैसा हड़पने वाले गिरोहों पर निगरानी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 5 आईपीएस अधिकारियों समेत 8 वरिष्ठ अफसरों की विशेष टीम गठित की है। इस टीम की कमान अपर मुख्य सचिव गृह शिव शंकर शुक्ला को सौंपी गई है।



प्रदेश में बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले

सरकार का मानना है कि प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साइबर अपराधी लोगों को कभी आसान लोन, अधिक मुनाफे वाले निवेश, फर्जी प्रॉपर्टी डील और ऑनलाइन ऑफर का लालच देकर ठग रहे हैं। वहीं कई मामलों में अपराधी खुद को पुलिस, बैंक अधिकारी या जांच एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को डराते हैं और खाते से पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। हाल के समय में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे मामलों में भी तेजी आई है, जहां लोगों को यह कहकर डराया जाता है कि उनके बैंक खाते का गलत इस्तेमाल हुआ है या उनके परिवार का कोई सदस्य किसी मामले में फंस गया है। घबराहट में लोग ठगों के बताए खातों में रकम भेज देते हैं।

लोगों को जागरूक करने बनेगी विशेष रणनीति - इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने वित्तीय नियामक संस्थाओं और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का फैसला किया है। इस टीम में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कोशल विकास, नगरीय विकास और पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित अधिकारी भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। अफसरों की विशेष टीम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष रणनीति तैयार करेगा, ताकि साइबर ठगी के नए तरीकों के बारे में समय रहते जानकारी दी जा सके और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

अतिक्रमण हटाने गई फॉरेस्ट-पुलिस की टीम पर पथराव

नेपानगर में जेसीबी ऑपरटर समेत 4 लोग घायल, 500 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी तैनात

बुरहानपुर। बुरहानपुर वनमंडल की नेपा रेंज के ग्राम झांझर में रविवार सुबह वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम बाहरी अतिक्रमणकारियों को हटाने पहुंची। इस दौरान करीब 11 बजे टीम पर पथराव हुआ, जिसमें वनकर्मियों सहित 4 लोग घायल हुए। एक जेसीबी चालक को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। टीम अभी जंगल में मौजूद है। लंबे समय से वन विभाग बाहरी अतिक्रमणकारियों को हटाने की योजना बना रहा था, लेकिन तारीख तय नहीं हो पा रही थी। रविवार से कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन झांझर में पथराव हो गया। इस अभियान में निमाड़ के 4 जिलों का वन अमला और स्थानीय पुलिस शामिल रही। इसके लिए शनिवार शाम बुरहानपुर पुलिस लाइन में फोर्स जमा की गई थी। बाहरी अतिक्रमणकारियों को विन्धित कर बेदखल कर रहे - डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने बताया कि नेपानगर रेंज में रविवार को बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बाहरी अतिक्रमणकारियों को विन्धित कर बेदखल किया जा रहा है। इसमें पुलिस, प्रशासन और बुरहानपुर के साथ खंडवा, खरगोन, बड़वाह के वनकर्मी शामिल हैं। करीब 500 से अधिक अफसर-कर्मचारी जेसीबी और अन्य संसाधनों के साथ फील्ड में हैं।



जेसीबी पर पथराव किया, स्टेशनरिंग हिला और जेसीबी पलटी - जिला अस्पताल में सीधी निवासी जेसीबी चालक कमल बंसल भर्ती हैं। अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों ने जेसीबी पर पथराव मारा, जिससे स्टेशनरिंग हिला और जेसीबी पलट गई। युवक के सिर में चोट आई और वह बहकर भागा। घायल ने बताया कि 150 से अधिक अतिक्रमणकारियों ने हमला किया, जिससे पुलिस और वनकर्मी भागे। उसे वनपाल विजय चोरे अस्पताल लाए, जहां चिकी प्रभागी सलीम खान ने बयान दर्ज किए। बुरहानपुर वनमंडल के एसडीओ अजय सागर ने बताया कि वन विभाग की टीम झांझर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया, जिसमें एक जेसीबी चालक घायल हो गया। चालक के सिर में चोट आई है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हालत बेहतर है। घटना में अन्य कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

बैठकों के जरिए जागरूक किया और बेदखली की योजना बनाई - बीते सालों में नेपानगर और नावरा रेंज में बड़े पैमाने पर वन कटाई हुई। बाद में विकास के लिए लाखों रूट-शूट और पीछे लगाए गए, जिन्हें पेड़ बनने में 15-20 साल लगेंगे। वन विभाग अब अतिक्रमण और कटाई रोकने के प्रयास तेज कर चुका है। ग्रामीणों को बैटकों के जरिए जागरूक किया गया और बेदखली की योजना बनाई गई। करीब द्वादश साल पहले जिले में वनों में बड़े पैमाने पर तबाही मची थी। बाहरी अतिक्रमणकारियों ने अधिकारियों के सामने पेड़ों की कटाई की थी। इसके बाद प्रशासन, पुलिस और वन विभाग ने नावरा रेंज में अभियान चलाकर 1000 से अधिक टपेरियां तोड़ीं और अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। बाद में गौधारापण हुआ। अब फिर से बेदखली का अभियान चल रहा है, क्योंकि पात्र के अलावा अपात्र लोग भी बस गए हैं। द्वादश साल पहले 17 दिन चली कार्रवाई के बाद वन विभाग ने नोटिस देकर अतिक्रमणकारियों को हटाने को कहा था, लेकिन कई लोग अब भी बसे हैं। अब ऐसे लोगों को कानूनी रूप से विन्धित किया गया है। वन अधिकारियों ने कहा कि पात्र लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जो अपात्र होकर 2005 से पहले का चलाकर रहे हैं और प्रमाण नहीं है, उन्हें हटाना जाएगा। सूत्रों के अनुसार खरगोन, बड़वाही और खंडवा से भी लोग यहां बसे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।

एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के 27 अप्रैल को प्रस्तावित विशेष सत्र में पहली बार संसद से पारित ना होने वाले बिल पर चर्चा होगी। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विस्तृत चर्चा होने जा रही है। महिला आरक्षण और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिससे सदन में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार इस विशेष सत्र के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को प्रमुखता से सामने रखेगी और महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा करेगी। वहीं,

कांग्रेस 2023 में पारित महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का सदन में संकल्प पत्र ला सकती है। बता दें केंद्र सरकार का सदन में महिला आरक्षण से जुड़ा लाया गया 131वां संविधान संशोधन बिल सदन में पारित नहीं हो सका। इसके बाद मध्य प्रदेश समेत देश में नारी शक्ति को लेकर सियासत गरमा गई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस समेत विपक्ष को नारी शक्ति का विरोधी बताते हुए आरक्षण लागू नहीं करने की बात कही। वहीं, कांग्रेस समेत विपक्ष ने भाजपा पर महिला आरक्षण को लेकर जनता को गुमराह करने और चुनाव में फायदा उठाने का आरोप लगाया। इसको

लेकर भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के आरक्षण का बिल पारित नहीं होने को लेकर अभियान के तहत जनता तक बात पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी एक दिवसीय विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिसमें महिला आरक्षण पर चर्चा होगी। विशेष सत्र को देखते हुए दोनों दलों ने अपने विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील और बड़े मुद्दे पर विधानसभा में होने वाली यह चर्चा आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। इसमें भाजपा



सिंधिया को हराने वाले केपी यादव का 'पावरफुल' कमबैक

अमित शाह ने पूरा किया अपना वादा, लोकसभा चुनाव के समय दिया था भरोसा

भोपाल। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉ केपी यादव, जिन्हें सिंधिया के भाजपा में आने के बाद गुना लोकसभा से टिकट काट दिया था। अब उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने निगम मंडल में जगह दी है, जिसे लोग अमित शाह के द्वारा दिया हुआ वचन पूरा करने के रूप में भी देख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में लगातार निगम मंडल की नियुक्तियां की जा रही हैं। ऐसे में लंबे समय से निगम मंडल में अपने नेताओं को जगह दिलाने के लिए एमपी में जोर आजमाइश के साथ ही नेता दिल्ली तक दौड़ लगा रहे थे। ऐसे में शनिवार की देर रात गुना लोकसभा के पूर्व सांसद डॉ. केपी यादव को मध्यप्रदेश स्टेट स्प्लाइज कॉर्पोरेशन लि. में संचालक नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को



गुना लोकसभा से डॉ. के पी यादव ने चुनाव हराया था और चर्चा में आए थे।

जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिरा कर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद चुने गए और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में

सिंधिया एवं केपी यादव के बीच दूरियां जारी

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं डॉक्टर केपी यादव में दूरियां जारी हैं। क्षेत्र में अक्सर सक्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया के शासकीय कार्यक्रमों में डॉ केपी यादव नदारद रहते हैं। वहीं क्षेत्र में होने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में डॉ केपी यादव सक्रिय भूमिका में नजर आए, जिससे क्षेत्र में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच भी राजनीतिक खींचतान की खबर आती रहती है।

महिला आरक्षण पर कांग्रेस पर भड़के सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री बोले-पांच पीढ़ियों ने रोके महिलाओं के अधिकार

भोपाल। भोपाल में रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने अलग अंदाज में नजर आए। वे अचानक वीआईपी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना और लोगों से संवाद किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर वहां मौजूद लोग उत्साहित दिखे। इस दौरान उन्होंने युवाओं और नागरिकों से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस नेतृत्व ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वार्डा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की कई पीढ़ियों ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर नकारात्मक वैया अपनया। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की वजह से महिलाओं को उनका अधिकार मिलने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री



मोदी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी मजबूती से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार तीसरे साल जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और इसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुएं, बावड़ियों और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम तेजी से किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार गेहूं के साथ-साथ चना और मसूर की भी खरीदी कर रही है, ताकि किसानों को बेहतर लाभ मिल सके।

एकता के संदेश के साथ जुटी भीड़, बच्चे फिलिस्तीन झंडे छपी हुई टी-शर्ट में नजर आए

ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि मौलाना इलाही पहुंचे भोपाल

भोपाल। भोपाल शहर में मुस्लिम समाज की एकता और भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से कोहेफिजा स्थित एम.आई.जी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 'इतेहाद-उल-मुस्लिमीन जलसा' जारी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे हैं, जिससे आयोजन स्थल पर एकजुटता का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ छोटे बच्चे फिलिस्तीन झंडे छपी हुई टी-शर्ट में नजर आए, जिसकी दूसरी तरफ ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का फोटो लगा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मौलाना डॉ. अब्दुल मजिद हकीम इलाही, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हैं, भी मौके पर पहुंच चुके हैं। उनके आगमन के साथ ही कार्यक्रम में उत्साह और बढ़ गया है। विभिन्न मसालक के उलेमा एक मंच पर मौजूद हैं और समाज में आपसी मतभेद खत्म कर 'सिर्फ उम्मत' की सोच को मजबूत करने का संदेश दे रहे हैं।

मानवता और हक के लिए खड़ा होना जरूरी- इतेहाद-उल-मुस्लिमीन जलसे में मप्र कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव शैलेन्द्र शैली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंतरराष्ट्रीय सम्मान वापस लेने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिस सम्मान को देने के तुरंत बाद ईरान पर हमला हुआ, वह मानवता पर 'काला धब्बा' है। ऐसे में भारत की गरिमा और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए उस सम्मान को लौटाया जाना चाहिए। शैली ने अपने संबोधन में ईरान और भारत के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान को वे 'पूर्वजों का देश' मानते हैं और दोनों देशों के



बीच गहरे सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। उन्होंने 1994 के संयुक्त राष्ट्र के उस घटनाक्रम का उल्लेख किया, जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन ईरान ने भारत का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि यह इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ईरान के साथ खड़ा होना मानवता, न्याय और मानवीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करना है। उनके मुताबिक, यह फासीवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद के

● नारी शक्ति के सशक्तिकरण पर होगी चर्चा ● भाजपा और कांग्रेस दोनों की रणनीति तैयार

की महिला विधायक और महिला मंत्री सदन में सरकार की योजनाओं, स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और सशक्तिकरण से जुड़े फैसलों को प्रमुखता से रखेंगे। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पार्टी की महिला विधायक यह सवाल उठा सकती हैं कि संसद से कानून पारित होने के बावजूद इसका लाभ महिलाओं को तो तत्काल क्यों नहीं मिल रहा है। साथ ही परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक आरक्षण लागू नहीं होने के मुद्दे को भी विपक्ष जोर-शोर से उठाने की तैयारी में है।

लोधी सम्मेलन में साथ दिखेंगे उमा और प्रहलाद

● भोपाल की शौर्य यात्रा से सियासी संदेश की तैयारी

भोपाल। भोपाल के जंबूरी मैदान में 28 अप्रैल को स्वतंत्रता संग्राम के भूले-बिसरे नायकों और जनजातीय वीरों को सम्मान देने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर शौर्य यात्रा आयोजित की जाएगी। क्रांतिवीर नर्मदा टाइगर हिरदेशाह लोधी के बलिदान दिवस पर होने वाले इस आयोजन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसे लोधी समाज के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।

सीएम के साथ उमा-प्रहलाद एक मंच पर

कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा मध्यप्रदेश, नर्मदा टाइगर हिरदेशाह शोध संस्था और गोंड महासभा द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल



अध्यक्षता करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मौजूदगी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, हालांकि उनका कार्यक्रम अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि वह उत्तराखंड प्रवास के बीच भोपाल पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। यदि उमा भारती और प्रहलाद पटेल एक मंच साझा करते हैं तो इसे लोधी समाज में उनके प्रभाव और भाजपा के भीतर नए राजनीतिक संकेतों के तौर पर देखा जा सकता है। उमा भारती हाल के महीनों में फिर से सक्रिय नजर आ रही हैं और 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर चुकी हैं।

प्रीतम लोधी प्रकरण के बाद बड़ी राजनीतिक चर्चा- इसी बीच पिछरे विधायक प्रीतम लोधी को लेकर भाजपा के नरम रुख ने भी चर्चाओं को हवा दी है। विवादित बयान के बावजूद पार्टी की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात के बाद प्रीतम लोधी ने खेद जताया था। जानकारों का मानना है कि यह आयोजन भाजपा नेतृत्व को लोधी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी का संदेश देने की कोशिश भी हो सकता है। उमा भारती पहले ही समाज को अपने हितों के आधार पर राजनीतिक निर्णय लेने की बात कह चुकी हैं। वहीं, 2023 विधानसभा चुनाव के बाद प्रहलाद पटेल का नाम मुख्यमंत्री पद की चर्चाओं में भी रहा था।

30 सीटों पर लोधी समाज का प्रभाव

मध्य प्रदेश की करीब 25 विधानसभा सीटों पर लोधी समाज का प्रभाव माना जाता है। खासतौर पर ग्वालियर-वंदल और बुंदेलखंड क्षेत्र की कई सीटों पर यह वोट बैंक चुनौती नतीजों को प्रभावित करता है। शिवपुरी जिले की चार विधानसभा सीटों की भी समाज की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि राजनीतिक दल, खासकर इस सामाजिक समीकरण को लेकर सतर्क रहते हैं। वहीं, आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इतिहास से मुन्धित होकर सम्मान देना है, जिन्हें पर्याप्त पहचान नहीं मिल सकी। शौर्य यात्रा में हिरदेशाह लोधी, गोंड राजा डेलन शाह, नरवर शाह, मधुकर शाह बुंदेला और गजराज सिंह समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों एवं जनजातीय योद्धाओं को याद किया जाएगा। प्रदेशभर के साथ अन्य राज्यों से भी समाज के लोगों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में यह आयोजन ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने के साथ-साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों से पहले लोधी समाज की ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है।

संपादकीय ये तो होना ही था

ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता की कोशिश भी विफल रही। हालांकि इसके आसार पहले से ही दिख रहे थे, क्योंकि वार्ता के लिए ईरान की बुनियादी शर्तों को मानने के लिए अमेरिका तैयार नहीं था और बिना इन शर्तों को मान्य किए ईरान बातचीत के लिए राजी नहीं था। पहले दौर में दोनों देशों के बीच सीधी बात तो हुई,लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जबकि इस बार पाकिस्तान की मध्यस्थता के बावजूद दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत नहीं हुई। ईरान ने उस पर से प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी, जिसे अमेरिका ने नहीं माना। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान को अपनी शर्तों का कामज थमा कर विदेश दौर पर निकल गए। तो दूसरी तरफ चर्चा न होने की स्थिति में टूट ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का दौरा रद्द कर दिया, जिससे बातचीत की उम्मीदें धूमिल हो गईं। हालांकि, दोनों देशों ने संवाद का रास्ता खुला रखने की बात कही है। वैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बात की थी। अरागची अमेरिका के प्रस्तावों पर तेहरान का फॉर्मल जवाब लेकर इस्लामाबाद पहुंचे, जिसमें ‘क्षेत्रीय स्थिति’ और सीजफायर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके पहले तेहरान ने साफ कर दिया था कि वह दौरे पर आए अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलेगा। कोई भी बातचीत इनडायरेक्ट होगी। ईरान की पहली शर्त है कि ईरानी बंदरगाहों और स्ट्रेटेंजिक रूप से अहम होमुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी हटाई जाए। लेकिन अमेरिका इस पर तैयार नहीं है। उसे लगा रह है कि ईरान पर दबाव बनाकर वो उसे वापस की की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर देगा। कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि खुद ईरानी नेतृत्व के भीतर जबर्दस्त अंतरूनी लड़ाई और कम्यूजन है. कोई नहीं जानता कि इंचारज कौन है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान में कड़पट्टी नेतृत्व हावी हो गया है, जो किसी भी कौमत्त पर संरेड करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अभी तक यह साफ नहीं है कि अमेरिका कूटनीति को लेकर वाकई गंभीर है या नहीं। दरअसल ईरान यह अच्छे तरह समझ चुका है कि लड़ाई रोकने और हार्मुज स्ट्रेट खुलवाना अमेरिका की मजबूरी ज्यादा है बजाय ईरान के। इसका एक बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपने ही घर में घिरना है। वो जितना बड़बोलापन दिखा रहे हैं, उतने ही फंसते जा रहे हैं। दूसरा कारण संवैधानिक है। अमेरिकी कानून के मुताबिक ईरान के साथ जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जोनाल्ड ट्रंप पर युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस (अमेरिकी संसद) से मंजूरी लेने का भी दावा है। ‘वॉर पावर्स जेजोल्शूशन’ (1973) के तहत ट्रंप प्रशासन को ईरान के खिलाफ आक्रामक सैन्य कार्रवाई के लिए 1 मई तक कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी, अन्यथा उन्हें सेना वापस बुलानी पड़ सकती है या युद्ध रोकना पड़ सकता है। अगर ऐसा न हुआ तो यह ट्रंप की नैतिक, सैन्य और कूटनीतिक हार भी होगी। ईरान इस बात को बखूबी समझता है, लिहाजा वह वार्ता को ज्यादा से ज्यादा समय तक चलाने की नीति पर काम कर रहा है। लेकिन बाकी दुनिया के लिए वार्ता के दूसरे दौर का विफल होना, इसलिए गंभीर चिंता का विषय है कि इससे ऊर्जा का वैश्विक संकट और गहराने को आशंका है। खासकर भारत जैसे देशों ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम ऊर्जा अभाव के लिए अभी भी होमुज स्ट्रेट पर काफी कुछ निर्भर हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों का आंतरिक संकट भी और गहराएगा, क्योंकि उनका तेल और गैस निर्यात तो टप है ही, जरूरी सामान का आयात भी लगभग बंद है।

‘फास्ट ब्रीडर’ तक भारत की निष्पत्तिक छलांग

मोदी मन की बात

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लेखक पत्रकार हैं।



दुनिया इस समय अस्थिरता के ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां ऊर्जा वैश्विक शक्ति संतुलन का आधार बन चुकी है। ईरान में जारी युद्ध और उसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। महंगाई की मार हर देश झेल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं, लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच भारत ने एक ऐसा रास्ता चुना है, जो आने वाले दशकों में उसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बना सकता है। यह रास्ता है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और विशेष रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक का।

रविवार को प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में भारत की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए विज्ञान और तकनीक की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा- ‘साथियों, भारत ने विज्ञान को हमेशा देश की प्रगति से जोड़कर देखा है। इसी सोच के साथ हमारे वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ रहे हैं। उनके प्रयासों से यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, एनर्जी सेक्टर को, हेल्थकेयर सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। खेती किसानों से लेकर आधुनिक इन्ोवेटर्स को भी भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ने बहुत मदद की है।’ प्रधानमंत्री का यह कथन वास्तव में उस व्यापक परिवर्तन की झलक है, जो भारत के

वैज्ञानिक प्रयासों के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। परमाणु ऊर्जा अब बिजली उत्पादन से आगे कृषि में उत्पादकता बढ़ाने, चिकित्सा में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज और उद्योगों में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए भी अहम भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख किया, जिसने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है।

उन्होंने कहा- ‘कुछ ही दिन पहले, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि से भारत का गौरव बढ़ाया है। तमिलनाडु के कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। दरअसल, क्रिटिकलिटी वह स्टेज है, जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ-सस्टेनिंग न्यूक्लियर चैन रिक्रियन में सफलता हासिल करता है। इस स्टेज का मतलब है रिएक्टर का ऑपरेशन फेज में पहुंचना। भारत की न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में यह एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है।’ और बड़ी बात ये भी कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। साथियों, इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। यह एक ऐसा सिस्टम है, जो ऊर्जा के उत्पादन के साथ-साथ भविष्य के लिए नया ईंधन भी खूद ही तैयार करता है। ‘ कलपक्कम में स्थापित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) का ‘क्रिटिकलिटी’ स्तर तक पहुंचना किसी भी दृष्टि से साधारण उपलब्धि नहीं है। यह वह क्षण होता है, जब रिएक्टर के भीतर परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया स्थिर और नियंत्रित रूप से स्वयं चलने लगती है। यहीं से ऊर्जा उत्पादन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि भारत आज जटिल तकनीकों को समझने और विकसित करने में इतना सक्षम हो चुका है कि उसे इस दिशा में किसी अन्य देश के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं

रह गई है। निश्चित ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक को समझना जितना जटिल है, उसका महत्व उतना ही व्यापक है।

दुनिया के कई विकसित देशों ने इस तकनीक को हासिल करने के लिए दशकों तक प्रयास किए। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस दिशा में अरबों डॉलर खर्च किए, किंतु विभिन्न तकनीकी और आर्थिक चुनौतियों के कारण वे इस तकनीक को व्यापक स्तर पर लागू नहीं कर सके। इसके विपरीत, भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद इस दिशा में सफलता प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक दृष्टि और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

भारत की इस सफलता के पीछे सात दशक की वैज्ञानिक यात्रा और दूरदर्शी सोच छिपी है। महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने जिस तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी थी, वह आज अपनी सार्थकता सिद्ध कर रही है। इस कार्यक्रम का पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम से ऊर्जा और प्लूटोनियम उत्पादन पर आधारित है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से अधिक ईंधन तैयार किया जाता है, जबकि तीसरे चरण में थोरियम आधारित रिएक्टरों के जरिए दीर्घकालिक ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है।

यहां जान लें कि भारत के संदर्भ में थोरियम का महत्व अत्यधिक है। देश में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, पर थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विष्व के कुल थोरियम भंडार का लगभग एक चौथाई हिस्सा भारत में पाया जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक इस थोरियम को उपयोगी ईंधन में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि तो होगी ही, साथ में भारत की विदेशी ईंधन पर निर्भरता भी कम होगी।

कलपक्कम में स्थापित 500 मेगावाट क्षमता वाला यह रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी

वागर्थ

महिला आरक्षण बिल नहीं, परिसीमन विधेयक गिरा है

खेल खेला था जो अटलजी के कार्यकाल में हुआ था। जो इस बिल का विरोध करने वाले लोग है या थे वे पिछड़े वर्गों के नाम पर इस कानून का विरोध कर रहे थे। हालांकि वे सत्ता के दोनों समूहों के साथ रहे हैं। पिछड़े वर्गों के वही दल याने उत्तरप्रदेश की मुलायम, अखिलेश की समाजवादी पार्टी, बिहार के लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस के साथ यूपीए गठबंधन में शामिल थे और बाद में स्व. शरद यादव और नीतीश कुमार जो यूपीए गठबंधन में भी रहे और भाजपा में एनडीए गठबंधन में भी सरकार में शामिल रहे। इनके विरोध का आधार दिखाने को यही था कि महिला आरक्षण में कोटा में, कोटा होना चाहिये। याने 33 प्रतिशत आरक्षण में पिछड़ी जातियों का आरक्षण अलग होना चाहिए। एससी/एसटी का आरक्षण तो संविधान में पहले से ही है। अतःरू बहुजन समाजवादी दल ने इस पर कोई विशेष भूमिका अखियार नहीं की। एक प्रकार से बीएसपी तटस्थ जैसी रही। जो लोग पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए महिला आरक्षण से अलग कोटा चाहते हैं उनका यह कहना है कि अगर वह यह नहीं होगा तो सवर्ग महिलायें ही सारे आरक्षण का लाभ लेंगी। पर क्या वास्तव में यह संशय का कारण ही इनके विरोध का कारण था या फिर वे दिमागीतौर पर महिलाओं के विरोध में हैं या फिर केवल इस निराधार बातों को उठकर पिछड़े वर्गों के नेता बनना चाहते हैं। सत्यता तो यह है कि वे केवल अपनी राजनीति चलाये रखना चाहते हैं। उसे जिंदा बनाये रखने के लिए लिए यह तर्क गढ़ रहे थे। कौन नहीं जानता कि श्री लालू यादव, जो अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा थे और एक अयोग्य मालिक या तानाशाह थे जो अपनी पत्नी को जो विधायक भी नहीं थी, उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे तो महिलाओं को आरक्षित सीटों में पिछड़े वर्गों की महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट नहीं दे सकते थे। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष स्व मुलायम सिंह यादव जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते थे व अपनी भूत को सांसद बना सकते थे, तो क्या वह अपने दल की महिलाओं को 33 प्रतिशत हिस्सेदारी नहीं दे सकते? इसी प्रकार सुश्री मायावती बसपा की सुप्रीमा हैं, अपने दल के टिकट जिसे चाहे दे सकती हैं इसलिये मुझे लगता है कि उनका विरोध केवल राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्गों को गुमराह कर उनका वोट लेने, उनका नेता बनने का हथकंडा मात्र है। स्व शरद यादव का इस विषय में संसद में दिया गया भाषण मैंने मीडिया पर देखा था। जिसमें श्री यादव ने उन्हें क्रांतिकारी सिद्ध करने के लिए सीता बनाने द्रौपदी की चर्चा की थी।

हालांकि यह भी उनकी बेईमानी है कि जिस महान नेता ने नारियों के पक्ष में यह तर्क आज से 70 साल पहले 50 के दशक में देना शुरू किया था उनके नाम का उल्लेख भी नहीं किया। वह महान नेता जो अपनी पत्नी को जो विधायक भी नहीं थी, उनको मुख्यमंत्री पर यह सभी नेता बन सके, सत्ता के पदों पर आ सके। चाहे मुलायम सिंह हो,लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, शरद यादव हो या अन्य हो। ये सभी डॉ. लॉहिया के क्रांतिकारी विचारों की सोझी पर चढ़कर ही सत्ता तक पहुंचे हैं। शायद उनका यह कारण है भी रहा होगा कि लॉहिया जी ने 1950 के कालखंड में देश में सभी महिलाओं, बहनों को पिछड़ा माना था,उस समय वे बरंगें में कैद थी इसलिए उन्होंने अपनी योजना कि पिछड़े पावे 100 में 60,में समूची

महिला वर्ग को शामिल किया और अपने कर्ण रूपी प्रयोगों से अधिकारा पिछड़ी, दलित महिलाओं को प्रतीक बनाया, व उन्हें अवसर दिया था।

ये लॉहिया जी ही थे, जिन्होंने ग्वालियर की महारानी के विरुद्ध सुक्खो रानी नाम की जमादानी को चुनाव में खड़ा किया था।बिहार में खेत में काम करने वाली महिलाओं को कक्कर टिकट दिलाया और उन्हें सांसद बनाया। सत्यता तो यह है कि लोहिया के विचार की क्रांतिकारिता का लाभ उठकर ये सत्ता पर बहुतेरे लोग पिछड़े वर्गों के शोषक और जातिवाद, परिवाकवादी बन गए। अपनी सूरक्षा और आधार के लिए पिछड़े वर्गों के लिए नकली और गैर जरूरी बहस चलती रहे तथा स्वर्गीय अटल जी से लेकर मनमोहन सिंह व श्रीमती सोनिया गांधी भी सभी महिलाओं के आरक्षण के लिए ऊपर से दिखावा करते रहे,परंतु अंतरात्मा से उसे असम्मत करने के प्रयास करते रहे।श्री नरेंद्र मोदी को 2023 में अवसर मिला था जब देश की संसद और राज्य सरकारों का गणित उनके पक्ष में था तथा वर्ष 2023 के महिला आरक्षण कानून यानी नारी वंदन कानून के नाम पर यह बिल लगभग सर्वानुमति से पारित हुआ था। अगर भाजपा और प्रतिपक्ष को ईमानदार इच्छा होती तो 2023 में ही इसे लागू कर देते तथा विधानसभा और लोकसभाओं के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू नहीं बिल पारित होने के बावजूद उन्होंने पारित कानून को लागू नहीं किया तथा यह कक्कर टाल दिया कि महिला आरक्षण अगली जगणपना और परिसीमन के बाद लागू करेंगे। इसका क्या औचित्य था? लगभग 27 साल से लटक कर रखा गया और बिल जब पारित हो गया था तो इसे तत्काल लागू कर महिलाओं को हिस्सेदारी देना चाहिए थी।

इसी प्रकार प्रतिपक्ष भी महिला आरक्षण के पक्ष में अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई पुरुष सांसद या विधायक अपनी सीट महिला को देने को तैयार नहीं है।इस पर मैंने उस समय भी कहा और लिखा भी था, कि सरकार इसे तत्काल प्रभाव से संसदीय क्रमानुसार लागू करे। यानी अगर लगभग 170 क्षेत्र महिलाओं को आरक्षित करना हो तो 1 से लेकर 170 तक प्रथम चरण में, फिर 5 वर्षों बाद 171 से 240 तक, और फिर तीसरे टर्म में बकाया को आरक्षित करना चाहिए। यह आसान तर्क था। परंतु महिलाओं का वोट सभी दल चाहते हैं तथा किसी भी दल में साहस नहीं है और ना कोई अपनी सीट छोड़ना चाहता है। इसलिए नाब प्रकरी के तर्क गढ़े जाते हैं और महिला आरक्षण बिल को त्याग दिया जाता है।इसे आगे की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है। सभी संसदीय दलों के पुरुषवादी नेतृत्व को अपना स्थान बचाना है। सी पी आर-सीपीएम आदि वाम दलों द्वारा यद्यपि हर बार महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया गया पर इसे गठबंधनों के अंदर या बाहर इसे मुद्दा नहीं बनाया गया। अगर इन दलों ने पूर्व में भी महिला आरक्षण वर्तमान में नारी वदन विधेयक लागू करने को कहा होता तब प्रथक प्रस्ताव लाये होते तो यू.पी.ए. सरकार को मानना पड़ता।

वामपंथी बिल पर सदन में मतगणना व अपने दल की ओर से बिल पर वोट की मांग करते तो या तो यूपीए/एनडीए के दलों को

उसका समर्थन करना पड़ता या फिर देश में उनकी पोल खुल जाती। परंतु वामपंथी दलों ने अभी भी यह नहीं किया। मेरी समझ में 2026 में प्रतिपक्ष ने भी सुविचारित रणनीति नहीं बनाई। अगर प्रतिपक्ष अपनी ओर से भी एक समांतर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर देता कि नारी वंदन विधेयक को अमुक लिथि से लागू किया जाए और उसे प्रस्तुत करते तो सरकार बेनकाब हो जाती या उसका जनता में विश्वास टूटता कि प्रतिपक्ष तो नारियों को 2026 में ही आरक्षण देना चाहता है और सरकार 8 साल का झुनझुन पकड़ा रही है। जनगणना और परिसीमन के साथ इस बिल का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। जनगणना और परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों की संख्या स्वयं बढ़ जाती है। एससी/ एस्पटी जाति के लिए जब आरक्षण किया गया था तब 1950 में सांसदों की संख्या कम थी, फिर जब संख्या बढ़ी तो तदनुसार आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई।

एक तो महिलाओं की आवादी सभी दल 50 प्रतिशत, पर 50 प्रतिशत तो दूर 33 प्रतिशत जो पहले ही है। 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी कम किए जाने का प्रस्ताव है उसे भी लागू नहीं कराना चाहता। और अब यह प्रस्ताव भी पिछले 30 साल से गेंद की भांति कभी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के पाले में फेंक देता है और प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को पाले में फेंक देता है।जो ताकतवर होता है,जो ज्यादा प्रचार करने की ताकत रखता है वह जीत जाएगा, परंतु देश की महिलाएं ठगी गई है और ठगी जाएगी और अंत में हार उन्हीं की होगी। महिलाओं को अब दलों से ऊपर उठकर अपने हकों के साथ खड़े होना चाहिए। वैसे संसद में इस सत्ता पक्ष के प्रस्ताव के असम्मत होने से अब देश में सत्ता पक्ष के पतन का मार्ग खुल गया है।सत्ता पक्ष का पड्यंत्र असम्भत भी हुआ और बेनकाब भी।

मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को यह समझ में आ गया है कि यह दांव अब हो गया है।उके खिलाफतथा दक्षिणी राज्यों के चुनाव में भी यह सत्ता पक्ष के खिलाफजाएगा।

अभी विपुरा में ट्रान्जबल प्राधिकरण की 28 सीटों पर हूए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल चार सीटों पर ही जीती है शेष 24 सीटों पर हारी है।

मेरी राय में अभी भी अवसर है कि-

- सरकार तत्काल नारी वंदन विधेयक को संसद के क्रमानुसार लागू करने की कार्यवाही करे।
- प्रतिपक्ष दलों में कोटा की मांग के बजाय, फिलहाल अपने दलों में तय करें कि वह अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षित सीटों का कम से कम 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को देगे तथा उनमें भी कम से कम 15 प्रतिशत अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को देगे। इनमें उनके परिवार या जाति का प्रभुत्व नहीं होगा।

प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि प्रतिपक्ष ने नारी वंदन बिल की भ्रूण हत्या कर दी है।जबकि तथ्य यह है कि यह महिला आरक्षण बिल था ही नहीं वह तो नारी वंदन अभिनियम पहले ही पारित हो चुका है। यह तो वास्तव में परिसीमन विधेयक जो महिला आरक्षण को आगामी 8 वर्षों तक लटकाने को लाया गया था और परिसीमन विधेयक की भ्रूण हत्या, आज जरूरी नहीं थी।

त्रिकालदर्शी त्रिफलानंद की भविष्यवाणी

वकावित

डॉ. प्रदीप मिश्र

त्रिकालदर्शी त्रिफलानंद, राष्ट्र में संपन्न हो रहे विभिन्न चुनावों के परिणामों को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। राजनीति के कुशल चित्रते ने आगामी चार मई का जो चित्र अरेखित किया है, वह मुझे आज ही साफ दिखाई दे रहा है।

मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि, चुनावों में अधिकांश उम्मीदवारों की पराजय हुई है। विजयश्री प्राप्त करने वाले कुछ ही सौभाग्यशाली हैं। विजेता भी मुझे दो तरह के दिखाई दे रहे हैं। पहले वे जो दल-प्रताप से विजयी हुए हैं। सत्ता के साम्यिसे वे ही लाभान्वित होंगे। दूसरे विजेता बस विजयी हुए हैं। उनका दल, निबल साबित हुआ है। वे विपक्ष में बैठकर सत्ता को दूर से निहारेंगे। चित्र में विजय रथ पर विजयी प्रत्याशी आरूढ़ है। प्रचार के दौरान विकास रथ कहलाने वाला वाहन, विजय के उपरांत विजय रथ कहलाना है। विजेता फूल-मालाओं से लदा हुआ है। वातावरण गुलाल से गुलज्जार है। चारों तरफ सत्ता की नजदीकियां चाहने वालों का हजूम है। बेसुरा सगीत बेरोकटोक, ऊंची आवाज में बजाया जा रहा है। लोग नाच रहे हैं। अधिकांश नृत्वक विभिन्न नशे के प्रभाव से प्रभावित हैं। जो नशा नहीं किए हैं, वे सत्ता के नशे में आज से ही गहरे उतराने लगे हैं। सारा वातावरण, सत्ता के

नैसर्गिक स्वरूप को उद्धोषित कर रहा है।

विजेता मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। वे बिना शर्म, अपनी विजय को सत्य की विजय बता रहे हैं। उत्साह में वे विपक्षी की पराजय को असत्य की पराजय कहते हैं। चुनाव-खर्च की सूची पर दृष्टिपात करते हुए विजेता कहता है कि, ‘जनता मेरा परिवार है। और अपने परिवार को संपन्न बनाने के लिए मैं आज से ही जुट पड़ूंगा।’

पराजित प्रत्याशी एक स्वर से कह रहे हैं , ‘ मैं जनादेश को विम्वततापूर्वक स्वीकार करता हूँ। छल, प्रपंच, धनबल, बाहुबल, से मेरे विरोधियों ने मुझे पराजित किया है। मैं अपने इस अन्याय के विरुद्ध न्यायालय में याचना करूंगा।’

अरे यह क्या? पराजित ही नहीं विजेता भी हिंसात्मक कृत्य में संलग्न हो गए हैं। दोनों अपने विरुद्ध मत देने वाले को कृतघ्न मान रहे हैं। मतदाता मार खा रहा है। मतदान को महादान मानकर वोट दिया तो आज उसकी जान सांसत में फंसी है।

जितने विजयी हुए हैं, उनमें से अधिकांश मंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए विजेता अपने दल में अब मंत्री पद अधिग्रहित करने के लिए सायास प्रयास कर रहे हैं। वे अपने संरक्षक नेताओं की गली के शवानों को सहलाने हुए, मंत्रीपद प्राप्ति की कटिन तपस्या में लीन हैं। तपस्या में कमी का प्रचलित अर्थ, पदच्युत होना है।

मैं त्रिकालदर्शी त्रिफलानंद वर्तमान में इतना ही देख पा रहा हूं। सारा कुछ देखते हुए दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। विश्राम की जरूरत है अब मुझे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MP/HIN/ 2003/ 10923,
Ph.No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. मुकेश असीमित

लेखक व्यंग्यकार हैं।

तो पार्टी के ‘हारने के कारणों’ के प्रवक्ता है! जो हौं, वक्तव्य देने की कला में निष्णात, पराजय के विश्लेषण में पारंगत। उनकी पार्टी का मूल सिद्धांत ही है हारना। चाहे पार्टी के विचारों की गुलाटी हो या हारने के बहाने, कुछ भी बदलना नहीं। पार्टी मैदान में उतरती ही इसलिए हैं क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई पार्टी जीत रही है, तो किसी को तो सामने खड़ा होना ही पड़ेगा हारने के लिए। अगर वे चुनाव ही न लड़ें, तो सामने वाली पार्टी की जीत को निर्विरोध ही मान लिया जाएगा,यह कहां का न्याय है?

हारते हैं, पर अंदाज अलग होता है! हर हार में जीत की संभावनाएं ढूंढने में माहिर! मान लींजिए, कोई तीसरी पार्टी उनसे भी बुरी तरह हार जाए, तो वे कह सकते हैं, ‘देखो, हम कम से कम उनसे तो



कानून और न्याय

एसआईआर प्रक्रिया-1
विनय झैलावत(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर
जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

सर्वोच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमान्य बागची और न्यायाधीश विपुल पंचोली की पूर्ण पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपीलौय न्यायाधिकरण का रुख करने को कहा। ये न्यायाधिकरण एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से बहिष्कार के खिलाफ अपीलें सुनने के लिए गठित किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि 65 याचिकाकर्ता चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। यह स्थिति विडंबनापूर्ण है क्योंकि, जो व्यक्ति चुनाव करा रहा है, वही मतदान नहीं कर पा रहा है। उनके ड्यूटी आदेशों में दर्ज ईपीआईसी नंबर अब हटा दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के नाम हटाना प्रथम दृष्टया मनमानी है।

न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही 5 अप्रैल को अपील दायर कर चुके हैं। इसलिए वे न्यायाधिकरण के समक्ष अपने उपायों का पालन करें। न्यायालय ने मामले का निस्तारण करते हुए उन्हें वहीं राहत पाने का निर्देश दिया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश बागची ने टिप्पणी की कि चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन मतदाता सूची में बने रहने का अधिकार अधिक मूल्यवान है और इस पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जिन व्यक्तियों की अपील 21 या 27 अप्रैल तक

चुनाव में पारदर्शी और निष्पक्ष पुनरीक्षण जरूरी

विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों की त्रुटिरहित सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन, इसमें सटीकता और समावेशिता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा है। फिर भी मतदाता अधिकार से वंचित होने और पूर्वाग्रह को लेकर चिंता बनी हुई है।

स्वीकार हो जाती है, उन्हें संबंधित चरण में मतदान की अनुमति दी जाए। लेकिन केवल अपील लंबित होने से मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा। रिपोर्टों के अनुसार, अपीलौय न्यायाधिकरणों के समक्ष लगभग 34 लाख अपीलें लंबित हैं। इनमें से पहले चरण में 138 मामलों का निपटारा करते हुए 136 मतदाताओं के नाम पुनः शामिल किए गए हैं।

निर्वाचन नामावली (जिसे मतदाता सूची या निर्वाचक रजिस्टर भी कहा जाता है) एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र और पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची है। इसका उपयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने तथा चुनावों के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है। मतदाता सूचियाँ भारत के चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत तैयार की जाती हैं। इसमें गैर-नागरिकों (धारा 16) को शामिल नहीं किया गया है। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को शामिल किया गया है जो सामान्यतः निर्वाचन क्षेत्र (धारा 19) में निवास करते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण केन्द्रित, समयबद्ध, घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है, जो प्रमुख चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन और सही करने के लिये बृथ स्तर के

अधिकारियों द्वारा संचालित की जाती है। यह प्रक्रिया नये पंजीकरण, विलोपन और संशोधन की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची सटीक, समावेशी और विसंगतियों से मुक्त हो।

कारणों के साथ किसी भी समय विशेष संशोधन करना भी शामिल है। एसआईआर का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का

अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार है, जब तक कि उन्हें आपराधिक दोषसिद्धि, विकृत मस्तिष्क या भ्रष्टाचार के कारण कानून द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया जाए।

मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मामले (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की व्यापक शक्तियों को बरकरार रखा। इसमें आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान का आदेश देना भी शामिल है। इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 329(बी) के अनुसार चुनावों के दौरान न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है। इसमें स्पष्ट किया गया कि यदि अनुच्छेद 327 और 328 के तहत कानून किसी भी पहलू पर मौन है तो भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि यद्यपि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, फिर भी असाधारण परिस्थितियों में चुनाव आयोग त्वरित और व्यावहारिक निर्णय ले सकता है। पूर्ववर्ती मतदाता सूची पुनरीक्षण देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग वर्षों में तथा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आयोजित किये गए थे। बिहार में सन् 2025 से पहले अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में आयोजित किया गया था। अनुच्छेद 327 संसद को विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार तथा अनुच्छेद 328 राज्य की विधानमंडल को उसके अपने चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है।

— (शेष अगले कॉलम में)

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

भारतीय राजनीति में दल-बदल की नई पटकथा: विचारधारा, अवसरवाद और लोकतांत्रिक संकट

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने यह कहा कि 'मैं सही आदमी हूँ, लेकिन गलत पार्टी में हूँ।' यह कथन भारतीय राजनीति के उस अंतर्विरोध को उजागर करता है, जहाँ व्यक्ति स्वयं को सही ठहराते हुए संगठन को दोषी ठहराता है। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल जैसे नेताओं की उपस्थिति इस निर्णय को व्यक्तिगत न रक्खकर सामूहिक स्वरूप देती है। जब यह दावा किया जाता है कि राज्यसभा में पार्टी के दो-तिहाई सांसद उनके साथ हैं, तो यह केवल एक इस्तीफा नहीं, बल्कि एक संगठित राजनीतिक पुनर्संयोजन का संकेत बन जाता है। दूसरी ओर, अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को 'पंजाबियों के साथ धक्का' बताया, जबकि संजय सिंह ने इसे 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा करार दिया। 'ऑपरेशन लोटस' शब्द अब भारतीय राजनीति में एक प्रतीक बन चुका है, जिसका उपयोग विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाने के लिए किया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक विस्तार के लिए विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाए गए आरोप राजनीतिक विमर्श को और अधिक तीखा बना देते हैं।

बताया, जबकि संजय सिंह ने इसे 'ऑपरेशन लोटस' का हिस्सा करार दिया। 'ऑपरेशन लोटस' शब्द अब भारतीय राजनीति में एक प्रतीक बन चुका है, जिसका उपयोग विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाने के लिए किया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक विस्तार के लिए विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाए गए आरोप राजनीतिक विमर्श को और अधिक तीखा बना देते हैं। हालांकि, इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह वास्तव में राजनीतिक दबाव का परिणाम है या फिर एक वैचारिक असहमति का स्वाभाविक निष्कर्ष? राघव चड्ढा का यह दावा कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है, एक गंभीर आरोप है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या यह असहमति अचानक उत्पन्न हुई, या यह लंबे समय से पनप रही थी? भारतीय राजनीति में यह प्रवृत्ति देखी गई

है कि जब नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, तब वे 'विचारधारा' का सहारा लेकर अपने निर्णय को वैधता देने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, इस प्रकार की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जनप्रतिनिधि अपने दल के प्रति निष्ठावान रहें और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दल-बदल न करें। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि यदि किसी दल के दो-तिहाई सदस्य एक साथ दल बदलते हैं, तो उन्हें अयोग्यता से छूट मिल सकती है। यही प्रावधान इस पूरे घटनाक्रम को संवैधानिक वैधता प्रदान करता है, भले ही नैतिक दृष्टि से यह विवादास्पद हो। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह कानून वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा करता है, या यह राजनीतिक अवसरवाद को वैधता प्रदान करता है? कई संवैधानिक

विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रावधान 'सामूहिक दल-बदल' को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत दल-बदल पर तो रोक है, लेकिन समूह में किए गए दल-बदल को स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार, यह कानून अपने मूल उद्देश्य से भटकता हुआ प्रतीत होता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव पंजाब की राजनीति पर पड़ सकता है, जहाँ भगवंत मारन के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार कार्यरत है। राज्यसभा के सांसदों का इस प्रकार दल बदलना न केवल पार्टी की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित करेगा, बल्कि यह राज्य के राजनीतिक संतुलन को भी बदल सकता है। इससे यह भी संदेह जा सकता है कि पार्टी के भीतर असंतोह गहरा है, जो भविष्य में और बड़े राजनीतिक बदलावों का कारण बन सकता है। राजनीतिक नैतिकता के संदर्भ में यह घटनाक्रम एक गंभीर संकट को उजागर करता है। जब नेता उस पार्टी को छोड़ते हैं, जिसके नाम पर वे जनता

से वोट मांगकर सत्ता में आए थे, तो यह मतदाताओं के विश्वास को आहत करता है। संजय सिंह द्वारा इसे 'विश्वासघात' कहना और राघव चड्ढा द्वारा इसे 'आत्ममंथन का परिणाम' बताना—दोनों ही अपने-अपने दृष्टिकोण से सही हो सकते हैं, लेकिन सत्य इन दोनों के बीच कहीं स्थित है। मीडिया की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण है। विभिन्न मीडिया संस्थान इसे अलग-अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे जनमत प्रभावित हो रहा है। सोशल मीडिया के इस युग में राजनीतिक नैटिव तेजी से बनते और बदलते हैं, और अक्सर तथ्य और भावनाएँ एक-दूसरे में घुलमिल जाती हैं। ऐसे में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि जनता सूचनाओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण करे।

अंततः, यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। लोकतंत्र केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं चलता, बल्कि यह राजनीतिक नैतिकता, पारदर्शिता और जनविश्वास पर आधारित होता है। यदि दल-बदल की यह प्रवृत्ति इसी प्रकार बढ़ती रही, तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल अपने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करें, नेताओं को केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य बना सकें। राघव चड्ढा का यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत या राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के उस संक्रमणकाल का प्रतीक है, जहाँ सत्ता और विध्वंस के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। आने वाले समय में यह देखा महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारतीय राजनीति इस चुनौती से उबर पाती है, या यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के मूल्यों को और अधिक क्षीण कर देती है।

किस्सा सन् 1854 की पेरी संधि का

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



ह संधि थी या आत्मसमर्पण? वह खरारनाक घुड़की थी या घेराबंदी? एक ओर था विश्व-परिदृश्य में ताजा-ताजा उभरा अपनी फिल्सलया फडकता आज़रजकों का राष्ट्र अमेरिका और दूसरी ओर था साहस और श्रम का धनी सामुराईयों का आत्मलौन देश जापान। अमेरिका की गुजारिश में धमकी का धोल था। पेरी ने कहा था- 'मानो या भुगतो', तो क्या जापान के सामने कोई और चारा नहीं था? उसके बंद कपाटों पर अमेरिकी दस्तक इतनी जबर थी कि उसने अपने द्वार खोल दिये थे। देखादेखी ब्रिटेन और रूस भी अमेरिकी कतार में खड़े दिखे, मगर जापान ने सबक लिया और अपने को ताकतवर और सुसज्ज करने में जुट गया। एक सौ तिहत्तर साल पहले की बात है। सन 1853। समुद्र की लहरों पर ब्रिटिश, डच, स्पेनी, फ्रेंच और पोचुगोज ताकतों का राज था। भारतीय उप-महाद्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के ताबे में था। योग्योपीय शक्तियों की निगाह जापान पर भी थी। पुर्तगाली, डच और स्पेनी जलपोतों का आना 16 वीं शती में ही शुरू हो गया था, किंतु सन 1639 में उन पर जापान के सम्राट का कहर टूटा। कैथोलिक प्रचारकों और वाणिज्यिक कर्तृत्वों के चलते सम्राट ने उनको निष्कासित कर दिया। अगली करीब दो सदियों तक चीन और हॉलैंड का जापान के साथ सीमित चार्टर व्यापार जारी रहा। दुनिया बदल रही थी और बदल रहा था नौवहन भी।

पालदार पोतों की जगह भापचालित पोत ले रहे थे। अमेरिका नये मसुबे बाँध रहा था। उसके अपने नौसैनिक बेड़े थे और सामने था खुला

समुद्र। वह जापान और चीन से वाणिज्यिक और दौत्य संबंध बनाने को आतुर था। अमेरिका की निगाह जापान पर टिकी तो टिकी रही। वजह कि वहाँ कोयले का अकूत भंडार था। उसे सुरक्षित हार्वर चाहिये थे, जहाँ उसके जलपोतों की मरम्मत हो सके और कोयले की आपूर्ति भी। मगर इसमें रोड़ा था। जापान के बंदरगाहों पर विदेशी नाविकों के साथ कठोर और अप्रिय बर्ताव के किस्से चारों ओर फैले हुये थे। सन 1830 के दशक में अमेरिका ने चीन में गुआंगझाऊ (कैंटन) से अनेक नौसैनिक जहाज भेजे, किन्तु जापान ने न तो उन्हें लंगर डालने दिया और न ही कोई सुविधा दी। अंततः सन 1851 में अमेरिकी राष्ट्रपति मिलर्ड फिल्मोर ने जापान के लिये एक नौ-मिशन की अनुमति दी। मकसद था जापान के बंदरगाहों पर टूटफूट के शिकार या क्षतिग्रस्त जहाजों को मरम्मत और ईंधन की सुविधा। साथ ही फंसे हुये नाविकों की सकृशल वापसी। अमेरिकी बेड़ा रवाना हो पाता कि जॉन ऑलिक रिलीव हो गये और उनकी जगह संभाली मैथ्यू पेरी ने। कमोडोर मैथ्यू पूर्णकालिक नेवी आफसर थे और उन्होंने मैक्सिको-अमेरिकी युद्ध में अपने चातुर्य का बखूबी प्रदर्शन किया था। अमेरिकी नेवी के स्टीम-युग में प्रवेश में भी उनकी अहम भूमिका थी।

कमोडोर पेरी सन् 1853 में अपने इस प्रशांत अभियान पर निकले। अमेरिका के लिये नये भूभागों की खोज में पहले वह दक्षिण-पश्चिम में रयुकमस और दक्षिण-पूर्व में बेनिन प्रायद्वीपों पर गये। उसके बाद उनके नेतृत्व में

अमेरिकी बेड़े ने इडो (टोक्यो) का रुख किया। उनके पास राष्ट्रपति फिल्मोर का जापानी सम्राट के नाम राजकीय पत्र भी था। जापान की आंतरिक दशा से अमेरिका की अनभिज्ञता का आलम यह था कि उसे यह नहीं ज्ञात था कि सम्राट की सत्ता बराये-नाम है और असली सत्ता ताकूगावा-शागुनात के हाथों में है।



अमेरिकी का खयाल था कि तोपों के बल पर जापान को झुकाया जा सकता है। कमोडोर पेरी ने पत्र के साथ-साथ सम्राट को उपहार भी सौंपे। इन भेंटों में था स्टीम-शिप का चालू मॉडेल। साथ में थे टेलीस्कोप, टेलीग्राफ और वाइन एंड लिंकर। अमेरिकी मांग थी कि जापान एक से अधिक पत्तन खोले, मांगी गयी सुविधाएँ दे अन्धशा कहर झेले। जाते-जाते वह कह गया कि वह फिर आयेगा। अगले ही साल

और अधिक दल-बल के साथ। गेंद अब जापानी पाले में थी। सम्राट पेरी की फिर आने की धमकी के निहितार्थ को बूझ रहे थे। अभी तक जापान का पाला तीर-तलवारों से पड़ा था। जापानी योद्धा तलवारों की धार तेज कर रहे थे, लेकिन तोपों और स्टीम शिपों का क्या जवाब था? टेलीग्राफ और टेलीस्कोप

था। शोगुनात हक्काबक्का थे कि क्या करें, क्या ना करें? कमोडोर पेरी अगले साल फिर आया। इस बार उसके बेड़े में आठ युद्धपोत थे। गनबोट पॉलिसी कसैटी पर थी, अलबत्ता पेरी को पूरा यकीन था कि वह सफल होगी। राष्ट्रपति फिल्मोर को भरोसा था कि पेरी की कामयाबी से कैलीफोर्निया के स्वर्ण समेत अमेरिकी सामानों के लिये जापान का बाजार खुल जायेगा। जापान के पास सूचनाओं का टोटा था। सूचनाओं का व्यापार। जापान आठ जुलाई, 1853 को पेरी का हट देख चुका था, जब उसने इडो खाड़ी के मुहाने से नागासाकी को जाने से इंकार कर दिया था। पेरी के धमकी देकर लौटने के बाद ही ताकूगावा लेयोशी की मृत्यु हो गयी और बागडोर उसके बीमार बेटे तामगावा लेसादा के हाथों में आ गयी। बागडोर अबे मासाहीरो के नेतृत्व में सिनियर कौंसिल के हाथों में थी। दीर्घमति अबे ने वरिष्ठों में रायशुमारी की तो दिलचस्प तौर पर मांग मानने या ठुकराने के पक्ष में बराबर-बराबर मत आये। सर्वत्र असमंजस था कि 11 मार्च, 1854 को बला की मानिंद पेरी फिर आ

धमका। उसका पैगाम साफ़ था कि बिना संधि वह लौटेगा नहीं। वार्ता के बजाय वह हार्वर के सर्वेक्षण जैसे कामों में जुट गया। अंततः आठ मार्च को वार्ता शुरू हुई। पेरी के आमनन पर अमेरिकी दल ने वैज्ञानिक दक्षता का प्रदर्शन किया तो जापानी दल ने सूभो कला का। 25 सूभो मुकाबलों का पेरी पर कोई असर नहीं पड़ा। अंततः जापान ने पेरी की लगभग सभी मांगें मान लीं। पेरी की टीम के बंदूकों के

चमत्कारिक प्रदर्शन ने जापानियों को भौचक कर दिया था। अंततः 31 मार्च, 1854 को काइको हिरोबा, याकोहामा में संधि पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुये। संधि का मजमून चार भाषाओं- अंग्रेजी, चीनी, जापानी और डच में तैयार किया गया। शिमोदा और हाकूदाते बंदरगाहों के मुँह अमेरिका के लिये खुल गये। जापान ने अमेरिकी नाविकों को सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ दे, उन्हें गिरफ्तार नहीं करने, मुद्रा विनियम, बंदरगाहों पर आवाजाही, शिमोदा में अमेरिकी दूत रखने पर हामी भरी।

उसने इस पर भी रजामंदी दी कि किसी भी अन्य राष्ट्र को प्रदत्त भावी सुविधा अमेरिका को भी मिलेगी। संधि के आशय पत्र की पुष्टि अनमने सम्राट कोमेई ने की। शोगुनात टोली का मुखिया रहा हायाशी अकीरा। ये सारे दस्तावेज जापान में आज भी सुरक्षित हैं। संधि से जापान सन 1600 से जारी सकोकू (अलगाव) युग से बाहर आ गया। संधि जापान और पश्चिमी देशों में वाणिज्य एवं इतर संपर्कों का बायस बनी। सत्ता सूत्र अगले ही दशक में सम्राट के हाथों में आ गये और जापान ने फौजी और औद्योगिक प्रगति की राह पकड़ी। जल्द ही जापान ने बतर्ज पेरी-संधि, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस से भी संधियाँ की। इस संधि ने परवर्ती हैरिस संधि की नींव रख दी। मैथ्यू पेरी की सन 1858 में 64 वर्ष की वय में मृत्यु हो गयी। वह अमेरिका की उस गनबोट नीति का नायक था, जो धौंस पर टिकी थी। उसकी संधि के निहितार्थ को लेकर इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं, लेकिन ऐसे इतिहासविदों की कमी नहीं है, जो इसे जापान के एशियाई महाशक्ति के तौर पर उभरने की प्रक्रिया का उत्प्रेरक मानते हैं।

कुत्ता एनिमल है और गाय?

सच ही तो कह रहा हूँ-

नितिन वेद्य

देश में पशु-अधिकारों पर चल रही बहस आज एक विचित्र मोड़ पर खड़ी है। कुछ संगठन और स्वयंभू 'एनिमल लवर' ऐसे सक्रिय दिखाई देते हैं मानो संपूर्ण पशु-जगत का प्रतिनिधित्व केवल कुत्ते ही करते हैं। उनकी संवेदनाएँ, उनकी अदालतों तक जाने वाली याचिकाएँ और उनके विरोध-प्रदर्शन लगभग पूरी तरह कुत्तों के इर्द-गिर्द ही दिखाई देते हैं। परंतु इस परिप्रेक्ष्य में एक गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है क्या पशु-अधिकारों का दायरा केवल एक प्रजाति तक सीमित होना चाहिए? 'न्याय के दरवाजे पर केवल एक पशु क्यों?' हाल के वर्षों में कुत्तों के अधिकारों, उनकी देखरेख और उनकी स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर अनेक याचिकाएँ उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची हैं। यह



संवेदनशीलता स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल तब उठता है जब वही सक्रियता गाय जैसे पशु के संदर्भ में लगभग अनुपस्थित हो जाती है।

देश के कई हिस्सों में अवैध गौ-परिवहन, अमानवीय वध, और सड़कों पर भटकती भूखी-प्यासी गायें-ये सभी मुद्दे वर्षों से समाज के सामने हैं, परंतु इनके लिए 'याचिकाकर्ताओं' की संवेदनाएँ शायद सुन हो जाती हैं। अदालतें तो खुली हैं, परंतु याचिकाएँ दाखिल करने में यह असमानता हमारे सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रर-निच-ह लगाती है।

सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता

भारतीय समाज में गाय का स्थान केवल धार्मिक आस्था भर का परिणाम नहीं है।

वह कृषि, पोषण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, हर स्तर पर उपयोगी है।

उसका दूध पोषण का प्रमुख स्रोत, गोमूत्र-जैविक कृषि और औषधि का आधार,

गोबर परंपरागत ऊर्जा और प्राकृतिक खाद का साधन है।

ऐसे पशु की उपेक्षा केवल भावनात्मक कमी नहीं, बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी नुकसानदायक है।

चयनात्मक संवेदना, समाज की नैतिक चुनौती जिस समाज में सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खुले में गंदगी करवाना सामान्य माना जाता है, वहीं किसी घर के बाहर गाय को ऐसा करते हुए शायद ही कोई देखता है।

यह केवल व्यवहार का अंतर नहीं, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि हम किस पशु को 'प्यारा' और किसे 'साधारण' समझकर उसके साथ व्यवहार तय करते हैं। संवेदना अगर निष्पक्ष है, तो उसे सभी पशुओं पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

परंतु जब करुणा विचारधारा, वर्ग या सुविधा देखकर तय की जाने लगे, तब वह 'करुणा नहीं पक्षपात कहलाती है।'

समाज को करुणा का संतुलन चाहिए। कुत्तों की सुरक्षा और अधिकार महत्वपूर्ण हैं-इस पर कोई विवाद नहीं।

किन्तु गाय जैसी उपयोगी और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजाति के मामले में उदासीनता केवल तर्कहीन ही नहीं, बल्कि सामाजिक असंतुलन भी है।

पशु-अधिकारों की बहस तब ही सार्थक होगी जब वह समग्र हो।

जब अदालतों में याचिकाएँ केवल एक प्रजाति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी जीवों के लिए हों जो मनुष्य की सह-अस्तित्व की धारा को आगे बढ़ाते हैं। यथायथ यही है, करुणा चयनात्मक नहीं, सार्वभौमिक होनी चाहिए। और गाय जैसे पशु के संरक्षण को न तो राजनीति का विषय बनाया जाना चाहिए, न उपेक्षा की।

श्री कृष्ण शरणम मम

जनपद

डिजिटल युग के नए दौर में जनसंपर्क की भूमिका और अधिक प्रभावी हो गई है

भोपाल। पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया, भोपाल चैप्टर द्वारा रविवार को एलएनसीटी यूनिवर्सिटी परिसर में 'राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस' पर विशेष व्याख्यान एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनसंपर्क और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने 'जनसंपर्क: लोकतंत्र का पाँचवाँ स्तंभ' विषय पर अपने विचार साझा किए।

लोकतंत्र का सजग प्रहरी है जनसंपर्क- पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया, भोपाल चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान में मुख्य वक्ताओं ने लोकतंत्र की मजबूती में जनसंपर्क की प्रभावी भूमिका और विशेषताओं पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक श्री गिरिजा शंकर ने कहा कि 'आज के दौर में जनसंपर्क केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि यह सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। पुराने दौर की अपेक्षा आज डिजिटल युग के नए दौर में जनसंपर्क की भूमिका और अधिक प्रभावी हो गई है। समाचार पत्र और टेलीविजन के बाद अब सोशल मीडिया के आने से जनसंपर्क की पहुँच अब दुनिया के किसी भी कोने तक संभव हो गई है।

बैतूल-आठनेर मार्ग पर मिला व्यक्ति, आईसीयू में भर्ती

बैतूल। आठनेर थाना क्षेत्र में बैतूल-आठनेर मार्ग पर फोरलेन ओवरब्रिज के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति गंभीर हालत में घायल मिला। उसे डायल 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है। घायल व्यक्ति ने पीली शर्ट और काला पैंट पहना हुआ है। उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल पहुँचने के बाद से वह बेहोशी की हालत में है और कई घंटे बीतने के बाद भी उसे होश नहीं आया है। अस्पताल चौकी प्रभारी एएसआई जयपाल रघुवंशी ने बताया कि घायल के पास किसी भी प्रकार का पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला है। घटनास्थल के आसपास कोई वाहन भी मौजूद नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह किसी वाहन से टकराया है या उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है।



व्याख्यान के विषय के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जनसंपर्क वह माध्यम है जो सबको आपस में जोड़कर लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है। प्रख्यात साहित्यकार डॉ. उर्मिला शिरीष ने रेखांकित किया कि 'संवाद की शुचिता ही लोकतंत्र की जान है। जनसंपर्क पेशेवर जब मानवीय संवेदनाओं के साथ तथ्यों को समाज तक पहुँचाते हैं, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होता है। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भोपाल के कुलगुरु (वाइस चांसलर) डॉ. नरेन्द्र कुमार थापक ने शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में जनसंपर्क के महत्व को बताते हुए कहा कि 'बदलते तकनीक के दौर में जनसंपर्क की जिम्मेदारी

और बढ़ गई है। यह एक ऐसा माध्यम है जो भातियों को दूर कर समाज को सही दिशा दिखाता है।'

विशिष्ट विभूतियों का हुआ सम्मान- समारोह में जनसंपर्क विभाग के उप संचालक श्री सुनील वर्मा, सहायक संचालक सुश्री निहारिका मीना और सुश्री हिमांशी बजाज को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 'लोक संपर्क सम्मान' से नवाजा गया। साथ ही, वरिष्ठ आंचलिक पत्रकार श्री मुन्ना लाल मिश्रा और चौधरी चरण सिंह युनिवर्सिटी मेरठ की रिसर्च एसोसिएट डॉ. बीनम यादव को लोक संपर्क से प्रदान किया गया।

महिला आरक्षण एवं महिला विरोधी नीतियों के विरोध में भोपाल में कांग्रेस का विशाल पैदल मार्च

भोपाल। आज भोपाल में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा सरकार की महिला विरोधी नीतियों के विरोध में एक विशाल पैदल मार्च आयोजित किया गया। यह पैदल मार्च प्लेटिनम प्लाजा से प्रारंभ होकर टीनशेड, टॉप एंड टाउन, न्यू मार्केट होते हुए रोशनपुरा चौराहा तक निकाला गया। मार्च के माध्यम से भाजपा सरकार की नीयत और महिलाओं के प्रति उसकी कथित उपेक्षापूर्ण नीतियों को जनता के सामने उजागर किया गया।

इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कालिलाल भूरिया, विधायकगण श्री फूल सिंह बरैया, श्री आरिफ मसूद एवं श्री पी.सी. शर्मा, मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुणाल चौधरी, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनवीश भागवत, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना बौरासी, पूर्व विधायक सुनीता पटेल, भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रवीण सक्सेना, भोपाल ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनोखी पटेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री यश घनचोरिया सहित एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आकस्मिक संदर्भ में विधानसभा सत्र बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी अपनी नीति स्पष्ट करते हुए मांग करती है कि देश को गुमराह करना बंद किया जाए और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने मांग की कि लोकसभा की सभी 543 सीटों पर महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए तथा मध्यप्रदेश विधानसभा में भी महिला आरक्षण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए, ताकि देश को एक स्पष्ट और सकारात्मक संदेश मिले। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सदन के भीतर विभिन्न नियमों के तहत आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व यह पहल पूर्णतः संवैधानिक प्रक्रिया के

अनुरूप की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं भाजपा से अपेक्षा की कि वे इस विषय पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए महिला आरक्षण प्रस्ताव को पारित करें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार यह प्रस्ताव पारित करती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी, अन्यथा जनता स्वयं इसका आकलन करेगी।

नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा और आरएसएस महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उजागर किया गया।



वास्तविक आरक्षण देने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक दल विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाकर 543 सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग करेगा और इसे केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि विशेष सत्र ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनोखी पटेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री यश घनचोरिया सहित एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आकस्मिक संदर्भ में विधानसभा सत्र बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी अपनी नीति स्पष्ट करते हुए मांग करती है कि देश को गुमराह करना बंद किया जाए और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने मांग की कि लोकसभा की सभी 543 सीटों पर महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए तथा मध्यप्रदेश विधानसभा में भी महिला आरक्षण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए, ताकि देश को एक स्पष्ट और सकारात्मक संदेश मिले। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सदन के भीतर विभिन्न नियमों के तहत आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व यह पहल पूर्णतः संवैधानिक प्रक्रिया के

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित

सेवानिवृत्त प्राचार्य व समाजसेवी स्व. महेश पचौरी के निधन पर जताई शोक संवेदनाएँ

बैतूल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल तथा केंद्रीय राज्यमंत्री व बैतूल-हरदा-हरसूद लोकसभा क्षेत्र के सांसद डीडी उडके ने रविवार की दोपहर में सेवानिवृत्त प्राचार्य एवं समाजसेवी स्व. महेश पचौरी के विकासनगर कालापाठा बैतूल स्थित निवास पर पहुंचकर आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाली उनकी धर्मपत्नी सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती शकुन्तला पचौरी व बिरिया समाजसेवी तुलिका पचौरी, बेटे आशीष पचौरी सहित उनके परिजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएँ जताईं और परिजनों को इस दुःख



को सहन करने की शक्ति देने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। गौरालंब है कि तब 24 अप्रैल को स्व. महेश पचौरी के निधन के पश्चात आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाने के कारण आज भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और केंद्रीय राज्यमंत्री



डीडी उडके उनके निवास पर पहुंचे और उन्होंने धर्मपत्नी श्रीमती पचौरी तथा उनके परिजनों को ढंडस भी बंधाया। इस अवसर पर पूर्व न्यायाध्यक्ष पार्षद आनंद प्रजापति, नागरिक बैंक के पूर्व अध्यक्ष अतीत पवार, स्व. महेश पचौरी के अनुज भ्राता

वरिष्ठ पत्रकार संजय पचौरी, पत्रकार कल्याण परिषद के महासचिव एवं स्व. महेश पचौरी के दामाद वरिष्ठ पत्रकार एवं पत्रकारिता के जानक शुकला, रंजना शुकला, प्रशांत राजोरिया, एडवोकेट उल्केश पचौरी आदि मौजूद थे।

200 जोड़ों ने जीवन भर के लिए थामा एक-दूसरे का हाथ, गुंजे मंगल गीत और बर्जी शहनाइयां

बैतूल। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस ग्राउंड रविवार को उस समय उत्सव स्थल में तब्दील हो गया, जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ। पूरे परिसर में शहनाइयों की मधुर धुन, मंत्रोच्चारण और मंगल गीतों की गूँज के बीच नवदंपतियों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। आकर्षक सजी वेदियों पर पारंपरिक विधिविधान से विवाह संस्कार संपन्न किए गए। कार्यक्रम की विशेष आकर्षण रही गाजे-बाजे के साथ निकली बारात, जिसका अगुवानी जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्पवर्षा कर की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उडके, प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल, विधायक आमला श्री योगेश पंडा उपस्थित थे। विशेष अतिथियों में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार, जनपद अध्यक्ष इमलाबाई जावलकर, नगर परिषद बैतूल बाजार अध्यक्ष दुर्गावती वर्मा, जनपद पंचायत आठनेर अध्यक्ष रोशनी उडके, नगर परिषद



आठनेर अध्यक्ष सुषमा मनोज जगताप, जनपद पंचायत आमला अध्यक्ष गणेश यादव, नगर पालिका आमला अध्यक्ष नितिन गाडे सहित जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय निकायों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री जनजातीय कार्य दुर्गादास उडके ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना और सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की चिन्ता कर पूरी भव्यता और गरिमा के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि

विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें पुरुष और प्रकृति एक होकर एकाकार हो जाते हैं और नव वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से सभी नव युवा दंपतियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया।

फिजूलखर्ची रुकेगी, बचत बनेगी भविष्य का सहारा: हेमंत- प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने सामूहिक विवाह समारोह में कहा कि आज 200 जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक अच्छे और प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए कहा कि

जनगणना 2027 द्वितीय चरण प्रगणक एवं सुपरवाइजर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

सोहागपुर। जनगणना 2027 द्वितीय चरण प्रगणक एवं सुपरवाइजर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सेंट पैट्रिक हॉल सेकेंडरी स्कूल परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सोहागपुर क्षेत्र के सभी नामित प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों ने सक्रिय रूप से सहभागिता निभाई। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जनगणना कार्य की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, डेटा संग्रहण की विधियों, मोबाइल, डिजिटल उपकरणों के उपयोग, तथा निर्धारित प्रश्नों को सही तरीके से भरने संबंधी विस्तृत सारांशित जानकारी दी गई। इसके साथ फोल्डर में आने वाली संभावित समस्याओं एवं उनके समाधान पर भी विशेष रूप से समझाई गई। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन अनुभवी मास्टर ट्रेनरों में बीआरसी राकेश रघुवंशी, रामकिशोर दुबे, विजेंद्र वर्मा, विपिन गिल्ला, राहुल तिवारी एवं जितेंद्र तिवारी ने प्रदान किया था। मास्टर ट्रेनरों ने प्रतिभागियों को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से कार्य की बारीकियों को समझाया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन में काफी सहायता मिलेगी। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी, तहसीलदार रामकिशोर झरदेव, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री बिजने नन्ददास ने सभी प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों को निर्देशित किया कि वे जनगणना कार्य को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न करें। ताकि सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें। प्रशिक्षण में कानूनगो राहुल साहू, निर्वाचन प्रोग्रामर अमितकुमार मिश्रा, संदीप कुशवाह, उमेश रघुवंशी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई कि वे जनगणना कार्य निष्ठा एवं ईमानदारी से करेंगे।

सोहागपुर। कतिया समाज के आराध्य देव शिव भक्त भूरा भक्त की जयंती इंदिरा वार्ड के मधुर मिलन गार्डन इंदिरा वार्ड में जयंती समारोह हार्मोन्स के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रवेश कर गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से सभी नव युवा दंपतियों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया।

फिजूलखर्ची रुकेगी, बचत बनेगी भविष्य का सहारा: हेमंत- प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने सामूहिक विवाह समारोह में कहा कि आज 200 जोड़े अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक अच्छे और प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को बधाई देते हुए कहा कि

कतिया समाज के आराध्य भूरा भक्त की जयंती पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र-छात्रियों को सम्मानित किया



छिंदवाड़ा में हुआ। विधायक के दौरान भूरा भगत जी को बुखार आ गया। तब संत जी सपली ग्राम सांगाखेड़ा में आराम के लिए रुक गए। तथा गुरु गोखनाथ की शेष मंडली आगे खाना हो गई। वहीं चौड़ागढ़ पर्वत पर भूरा भगत जी को शिव जी के साक्षात् दर्शन हुए थे। शिव भक्त संत भूरा भक्त जी ने ग्राम सांगाखेड़ा में स्थाई बनाकर रहने लगे। भगवान शिव जी की कृपा से संत जी क्षेत्रवासियों के दुख का निदान अपनी धूनी की

भभूती से करते थे। आज भी ऐसी मान्यता है जो भी व्यक्ति शिव के दर्शन करने चौड़ागढ़ जाते है। तो पहले भूरा भगत के दर्शन करने के उपरांत ही भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। इसी मान्यता के अनुसार महाराष्ट्र नागपुर क्षेत्र के श्रद्धालु पहले ग्राम सांगाखेड़ा जाकर भूरा भगत जी दर्शन करते हैं। बाद में चौड़ागढ़ जाकर भगवान भोलेनाथ शिव के दर्शन करते हैं। इसी अवसर पर अतिथियों ने वर्ष 2025-26 में कक्षा 10

वी और 12 वी में प्रथम श्रेणी में पास होने वाले 22 छात्र, छात्राओं को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर चंदनसिंह बेलवंशी, परमसुख पटारिया, रमेश अरसे, हरलाल बेलवंशी, रामेश भनारिया, रत्नेश नागवंशी, संतोष बेलवंशी, रामदयाल जागवंशी, शंकर लाल आरसे, रामाधार नागेश, शंकरलाल नायक, देवेंद्र जवांर अनिल जागवंशी, कमलेश ब्रह्मवंशी, लालबहादुर आमरवंशी, कमलेश, देवकिशन आदि सहित भारी संख्या में महिलाएं एवं ग्रामीण सजातीय बन्धु जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रवण भनारिया ने एवं आभार आयोजक पार्षद धर्मदास बेलवंशी ने किया।

सामाजिक भंडार एवं प्रसाद वितरण के बाद में सामाजिक बन्धुओं श्रवण भनारिया, अनिल जागवंशी, शिवन बेलवंशी अथवा आमरवंशी आदि ने रत्नेव स्टेशन परिसर में बजर, बेसहारा, निधन और परिक्रमावसियों के लिए राम रहम रोटी बैंक के माध्यम से भोजन की व्यवस्था कराई।

मध्यप्रदेश विधान सभा के विशेष सत्र पर विशेष पार्ट-1

‘नारी शक्ति’- ‘आधी आबादी’ का नेतृत्व: सत्ता नहीं, मध्यप्रदेश संवेदना का सदन

भोपाल। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा में 27 महिला विधायकों की मौजूदगी केवल चुनावी जीत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन 27 संघर्षों की कहानी है जिन्होंने ‘घर की दहलीज’ और ‘सदन की कुर्सी’ के बीच के फासले को अपनी जीवन्तता से मिटाया है। इस बार के सदन में महिला शक्ति का एक ऐसा गुलदस्ता सजा है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर से लेकर पूर्व राजधानी की परंपराएं और युवा जोश से लेकर अनुभवी विजन तक सब कुछ शामिल है। चूल्हे की आंच से सदन की दहलीज तक: मध्यप्रदेश की राजनीति में ‘ममत्व’ और ‘मजबूती’ का नया दौर देखने को मिल रहा है।

मौजूदा विधानसभा में इस बार जो 27 ‘माननीय’ महिलाएं बैठी हैं, उनके पास केवल नीतियां बनाने का अधिकार नहीं है, बल्कि उनके पास उन लाखों महिलाओं की उम्मीदें हैं जो आज भी राजनीति को दूर का सपना मानती हैं। इस बार की ‘नारी शक्ति’ में संवेदनशीलता और कड़े प्रशासनिक फैसलों का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

सदन में जब संपत्तियां उठके (भाजपा) खड़ी होती हैं, तो वह केवल एक कैबिनेट मंत्री नहीं, बल्कि उस अक्षय साहस का प्रतीक होती हैं जिसने कभी दिहाड़ी मजदूर कर अपना जीवन बिताया था। एक मजदूर से लेकर राज्य सभा सदस्य और अब कैबिनेट मंत्री तक का उनका सफर यह बताता है कि संघर्ष

की मिट्टी से उज्जा नेतृत्व कितना मजबूत होता है।

कृष्णा गौर की भोपाल की गोविंदपुरा सीट से 1.06 लाख वोटों की ऐतिहासिक जीत दर्ज

प्रियंका पैंची 31 साल की प्रियंका पैंची (भाजपा) इस विधानसभा का सबसे युवा चेहरा हैं। उन्होंने चाचाजू में 5 बार के सांसद और दिग्गज नेता लक्ष्मण सिंह को हराकर यह बड़ा संदेश दिया है।

जहाँ निर्मला भूरिया 5 बार की जीत के साथ सदन में आदिवासी हितों की बात कर रही हैं, वहीं अनुभा मुंजारे ने बालाघाट में एक कढ़ावर मंत्री को हराया है

‘आधी आबादी’ का नेतृत्व: कुल महिला विधायक: 27 (21 भाजपा, 6 कांग्रेस)

महिला विधायकों में सुश्री मीना सिंह मांडवे (मानपुर) सबसे वरिष्ठ हैं, जो 6वीं बार सदन की सदस्य बनी हैं। उनके बाद कुमारी निर्मला भूरिया (पेटलावर) का स्थान है, जो 5वीं बार निर्वाचित हुई हैं। उधर श्रीमती सुमित्रा, कविता पाटीदार और श्रीमती माया विक्रमसिंह नारोलिया राज्य सभा की शोभा बढ़ा रही हैं। श्रीमती सावित्री ठाकुर, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार में महिलाओं के हितों की रक्षा मुस्तैदी से कर रही हैं वहीं श्रीमती लता बान्खेड़े, हिमांदा सिंह, और श्रीमती संघ्या राय

लोकसभा में महिलाओं और मध्यप्रदेश की आवाज बनकर खड़ी हैं।

यह पहली बार है जब प्रदेश की प्रशासनिक बागडोर में भी महिलाओं का कद बढ़ा है। जहाँ 17 जिलों की कमान महिला कलेक्टर संभाल रही हैं, वहीं सदन में ये 27 महिलाएं एक ऐसी दीवार की तरह खड़ी हैं जो केवल राजनीति नहीं करतीं, बल्कि रिस्तों की गर्माहट के साथ जनसेवा को प्राथमिकता देती हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा का यह स्वरूप बताता है कि अब राजनीति और प्रशासन केवल पुरुषों का मैदान नहीं रही, यहाँ अब ‘बेटों, बहन और माँ’ के नजरिए से प्रदेश के भविष्य की इबारत लिखी जा रही है। वहीं 17 कलेक्टर और एक कमिश्नर के पद पर तैनात हैं।

आधी आबादी का पूरा शासन: मध्यप्रदेश में पहली बार 17 ‘लेडी कलेक्टर’ के पास जिलों की कमान

मध्यप्रदेश के विभिन्न 17 जिलों में तैनात महिला कलेक्टर हैं - खरगोन, सुश्री भव्या मित्तल, बडवानी, श्रीमती जयति सिंह, आलीगंजपुर, श्रीमती नीतू माथुर, रतलाम, सुश्री मिशा सिंह, शाजापुर, सुश्री ऋजु बाफना, आगरा मालवा, श्रीमती प्रीति रावत, मंडसौर, सुश्री अदिति गर्ग, ग्वालियर, श्रीमती रूचिका चौहान, श्यापुर, सुश्री शीला दाहिमा, मेहर, श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, उमरिया, श्रीमती राखी सहाय, सागर, श्रीमती प्रतिभा पाल, पन्ना, श्रीमती रुधा परमार, निवाड़ी, श्रीमती जमुना भिडे,

नरसिंहपुर, श्रीमती रजनी सिंह, सिवनी, श्रीमती नेहा मोना, डिण्डोरी, श्रीमती अंजु पवन भदौरिया। श्रीमती सुरभि गुप्ता भी हैं, जो शहडोल की कमिश्नर हैं।

मध्यप्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल के दौरान नारी शक्ति को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है। प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब 17 जिलों की कमान महिला कलेक्टरों के हाथों में सौंपी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि महिलाएँ किसी भी कार्य को अधिक जिम्मेदारी, पारदर्शिता और तीव्र गति से पूरा करती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में रानी दुर्गावती और देवी अहिल्याबाई होल्कर के शासनकाल को रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि सत्ता के साथ-साथ प्रशासनिक क्षेत्र में भी महिलाओं का कद बढ़ा है। सरकार में जहाँ 5 महिला मंत्री (संपत्तियां उठके, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, प्रतिभा बागरी और राधा सिंह) नीतिगत निर्णय ले रही हैं, वहीं ये महिला कलेक्टर जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत कर रही हैं।

यह बदलाव मध्यप्रदेश की राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं, बल्कि उनके निर्णायक नेतृत्व की पहचान बन रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने सुना मन की बात कार्यक्रम का 133वां एपिसोड

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां एपिसोड सुना। इस दौरान गौरव पांडेय, वार्ड पार्षद राजीव शर्मा, डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, प्रदीप सोहगीरा, कुंवर बहादुर सिंह, विजय शुक्ल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि मन की बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक मासिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे से प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ-साथ दूरदर्शन, यूट्यूब सहित विभिन्न न्यूज पोर्टल्स पर भी लाइव सुना और देखा जा सकता है। यह कार्यक्रम हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय



भाषाओं और बोलियों में अनुवादित कर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 से हुई थी। तब से यह अनवरत रूप से जारी है।

इस रविवार के कार्यक्रम को मिलाकर इसके 133वें एपिसोड पूरे हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने अप्रैल 2023 में अपने 100 एपिसोड पूरे किए थे।

स्टेशन पर यात्रियों को स्वच्छ और ठंडे जल की सेवा दी

बैतूल। गर्मी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और प्यास को पानी पिलाना सबसे बड़ी सेवा और धर्म माना गया है। ट्रेन स्टेशनों पर कुछ मिनटों के लिए ही रुकती है ऐसे में यात्री उतरकर पानी नहीं भर पाते हैं। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एवं गायत्री परिवार चोड़ाडोंगरी के संयुक्त तत्वावधान में रेल यात्रियों के लिए निशुल्क जल सेवा प्रदान की गई। चोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन पर दोपहर के समय ट्रेनों में यात्रियों को सैकड़ों लीटर स्वच्छ एवं ठंडा पानी पिलाया गया। जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिली। सेवा कार्य यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी और सराहनीय रहा। कार्यक्रम में ब्लॉक समन्वयक, मप्र जन अभियान परिषद एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के संयोजक संतोष राजपूत, गायत्री परिवार के डॉ. मनोज पाटणकर श्री दशरथ एवं गायत्री परिवार की सदस्य



बीएसडब्ल्यू और एएसडब्ल्यू कोर्स के परामर्शदाता के मार्गदर्शन में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर विजय कुमार महतो, जितन प्रजापति, संगीता उचडे सहित दोनों कक्षाओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे एवं सभी ने सेवा कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाई। ब्लॉक समन्वयक संतोष राजपूत ने आभार व्यक्त किया।

सक्षिप्त समाचार

शासकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

हरदा (निप्र)। वन स्टॉप सेंटर हरदा द्वारा शुक्रवार को प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की प्रभारी प्रशासक, श्रीमति अभिलाषा पटेलिया एवं केस वर्कर सुश्री रितु राजपूत ने छात्र-छात्राओं को महिला एवं बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा, बाल विवाह निषेध, रहेज प्रथा उन्मूलन तथा राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही ‘हब फॉर एंपावरमेंट’ के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित स्वरोजगार योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर द्वारा उपलब्ध सेवाओं परामर्श सहायता, विधिक सहायता, आश्रय सहायता, चिकित्सा सहायता एवं पुलिस सहायता की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, आपातकालीन सेवा 112 एवं विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्प लाइन 15100 के बारे में भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदा के प्रभारी प्राचार्य श्री शरद मालवीय, शिक्षकगण एवं वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ मौजूद रहा।

कलेक्टर के निर्देशानुसार अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्यवाही

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा जिले में अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने समस्त संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि जिले में स्थाई एवं अस्थायी सभी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को सख्ती से हटाना चाहिए तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड में सक्रियता दिखाएं और अवैध अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों के परिपालन में गुरुवार को नर्मदापुरम नगरीय क्षेत्र में नहर के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही तहसीलदार नर्मदापुरम, नगर पालिका नर्मदापुरम एवं नहर विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई। कार्यवाही के दौरान नहर क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण को हटाने हुए संबंधित स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अंतर्गत जिला सतर्कता एवं मौनीटरींग समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मौनीटरींग समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता, अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा एएसपी श्री कमलेश कुमार भी उपस्थित रहे। बैठक में माह जनवरी 2026 से मार्च 2026 की अवधि में प्राप्त एवं निराकृत प्रकरणों तथा इसी अवधि में थानों में दर्ज प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पीड़ितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रकरणों की जांच में तेजी लाकर स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक श्री सीपी सोनी ने माह जनवरी 2026 से मार्च 2026 की अवधि में प्राप्त तथा निराकृत प्रकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति अंतर्गत कुल 155 प्रकरणों में 104.85 लाख रु राशि वितरित की गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के 68 प्रकरणों में 75 लाख रु की राशि स्वीकृत की गई है। बैठक में संबंधित अधिकारी और समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे।



आठवें पोषण पखवाड़े का समापन, पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र

नर्मदापुरम (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग, नर्मदापुरम ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत आठवें पोषण पखवाड़े का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन परियोजना कार्यालय में किया गया, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पौष्टिक व्यंजनों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विभिन्न पोषणयुक्त रेसिपीज प्रस्तुत की गईं, जिन्हें उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने सराहा। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि श्रीमती सीमा तिवारी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती तुषि त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री ललित डेहरिया, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कौरव एवं समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त परियोजना अधिकारी नर्मदापुरम ग्रामीण श्री

प्रमोद गौर, परियोजना अधिकारी नर्मदापुरम शहरी श्रीमती प्रीति यादव, समस्त पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय सहभागिता की। संयुक्त संचालक श्रीमती तुषि त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदर्शनी में प्रदर्शित पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपीज को गंभीरता से ध्यान देकर कड़ा कि इन पौष्टिक व्यंजनों को घर-घर में अपनाया जाए, ताकि यह दैनिक आहार का हिस्सा बन सके और समाज को कुपोषण एवं विभिन्न बीमारियों से मुक्ति मिल सके। उल्लेखनीय है कि पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में मातृ एवं शिशु पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं जन-जागरूकता से संबंधित विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इटारसी में 8वें पोषण पखवाड़ा का गरिमामय समापन

नर्मदापुरम (निप्र)। इटारसी परियोजना अंतर्गत 8वां पोषण पखवाड़ा 9 अप्रैल से समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत मातृ एवं शिशु पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों संचालित की गईं। गुरुवार को इसका समापन कार्यक्रम रामगढ़ शाला, पुरानी इटारसी (वार्ड 6) में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री निर्मल सिंह राजपूत एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री निलेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, वहीं श्री आर. सोनकर (शिक्षक), श्री रमेश जगदेव, आदर्श मिश्रा (सुपरवाइजर, संगत संस्था) एवं श्रीमती रितु मेहरा (सीएमओ) की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान किशोरी बालिकाओं एवं ग्रामीण महिलाओं के बीच पोषण (पौष्टिक व्यंजन) प्रतियोगिता तथा पोस्टर/नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पोषण प्रतियोगिता में संघ्या मिश्रा ने प्रथम, रजिया खान ने द्वितीय एवं रेशमा बानो ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि नारा लेखन प्रतियोगिता में कु. मुस्कान (पिता - श्री संतोष मालवीय) प्रथम, कगना (पिता - बसंत कौर) द्वितीय एवं रितिका (पिता - कपिल बाघमारे) तृतीय स्थान पर रहीं। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने पोषण पखवाड़ा जैसे अभियानों को समाज में जागरूकता बढ़ाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए

प्रतियोगिताओं में दिखा उत्साह



माताओं एवं बच्चों के बेहतर पोषण के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। अनुविभागीय अधिकारी श्री शर्मा ने योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही तक पहुंचाने को प्रशासन की प्राथमिकता बताया तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की। सीएमओ श्रीमती रितु मेहरा ने पोषण आहार प्रदर्शनी को जागरूकता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया, वहीं संगत संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा पोषण एवं प्रारंभिक मस्तिष्क विकास पर उपयोगी जानकारी प्रदान की गई।

प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने पखवाड़े के दौरान किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कुपोषण मुक्त समाज के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम में विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सक्रिय सहयोग रहा।

कैम्पस ड्राइव में 9 विद्यार्थियों का अंतिम चयन हुआ

हरदा (निप्र)। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हरदा में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए पालीवाल बौल्ड इन्फ्रा. का कैम्पस ड्राइव आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉ. अभिरुचि सिंह ने बताया कि इस कैम्पस ड्राइव में अंतिम वर्ष के सिविल ब्रांच के करीब 19 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिससे 9 विद्यार्थियों का अंतिम चयन हुआ।

महिलाओं ने संभाली जल गंगा संवर्धन अभियान की कमान

डूंडादेह में श्रमदान कर दिया संरक्षण का संदेश

नर्मदापुरम (निप्र)। जल संरक्षण को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद नर्मदापुरम द्वारा कलेक्टर के निर्देशन में जिले भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोहागपुर विकासखंड के ग्राम डूंडादेह में महिलाओं ने अभियान की जिम्मेदारी संभालते हुए मिसाल पेश की। पलकामति नदी पर आयोजित जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम में नवांकुर संस्था मित्र संघ के प्रमुख कमल किरार के नेतृत्व में ग्राम की नवीन

महिला प्रस्फुटन समिति ने सक्रिय भागीदारी की। जन अभियान परिषद की प्रस्फुटन योजना के तहत गठित इस समिति की महिला सदस्यों ने नदी तट पर श्रमदान कर जल संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। श्रमदान से पहले प्रस्फुटन समिति की महिलाओं ने नर्मदा जी के गीत गाते हुए पूरे ग्राम में रेली निकाली। रेली के माध्यम से ग्रामीणों को जल बचाने और नदियों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर जन अभियान परिषद के विकासखंड



समन्वयक किशोर कदोले भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला कार्यकर्ताओं को जल संरक्षण एवं संवर्धन की शपथ दिलाई गई।

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य अभियानों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए सीएमएचओ और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं तथा अभियानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों, एचपीव्ही

जिले में 97.30 प्रतिशत एचपीव्ही वैक्सीनेशन पूर्ण



वैक्सीनेशन, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, एनसीडी कार्यक्रम, आईडीएसपी, मलेरिया, क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, लेप्रोसी तथा सीएम हेल्पलाइन की विस्तृत समीक्षा की गई।

उन्होंने एचपीव्ही वैक्सीनेशन की समीक्षा के दौरान 97.30 प्रतिशत वैक्सीनेशन पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांघी बीएमओ को शीघ्र शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिले में विकासखंड सिलवानी, उदयपुरा, बेगमगंज, औबेदुल्लागंज, बरेली तथा गैरतगंज में शत-प्रतिशत एचपीव्ही वैक्सीनेशन पूर्ण हो गया है तथा सांघी विकासखंड 85.08 प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ है। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने एएनसी रजिस्ट्रेशन लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जिला एवं विकासखंड के अधिकारियों द्वारा गृह भेंट कर उपचार करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि यदि प्रकरण में किसी व्यक्ति की लापरवाही पाई जाती है तो कठोर कार्यवाही की जाए। एनआरसी में डिस्चार्ज बच्चों का समय-समय

पर फॉलोअप भी लिया जाए। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में आयुष्मान कार्ड लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए सीएमएचओ, सिविल सर्जन तथा बीएमओ को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का प्राथमिकता से त्वरित निराकरण किया जाए। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए सीएमएचओ निर्देशित किया। जिले में 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाने हेतु समस्त विभागों की सहभागिता करते हुए प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश दिए।

पंचायतों, वार्डों में अब नहीं लगेंगे सोलर लाइट सोलर हाईमास्ट

ऊर्जा विभाग की कलेक्टरों को चिट्ठी कहा- सरकार का पैसा बर्बाद होता है

भोपाल। एक ओर लोगों को सोलर एनर्जी के अधिकाधिक उपयोग के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है, वहीं दूसरी ओर शासन ने यह तय किया है कि प्रदेश में पंचायतों और शहरों के वार्डों में अब सोलर लाइट, सोलर ट्री, हाईमास्ट और सोलर स्टड नहीं लगाए जाएंगे। ऊर्जा विभाग ने विभाग कलेक्टरों से कहा है कि शहरों, वार्डों और पंचायतों में ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सफाई



नहीं होने से ये बेकार हो जाते हैं। इसलिए इन उपकरणों को सरकारी पैसा खर्च कर नहीं लगाया जाए ताकि शासन का नुकसान रोका जा सके। ऊर्जा विकास निगम ने मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में हुए फैसले के मुताबिक स्थानीय निकायों में सोलर लाइट, सोलर ट्री, हाईमास्ट और सोलर स्टड जैसे उपकरण नहीं लगाए जाएं। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे जिलों में पंचायतों और शहरी वार्डों में इन उपकरणों का शासन के खर्च से नहीं लगाने दें ताकि शासन के पैसे की बर्बादी को रोका जा सके। इन हालातों को देखते हुए ही शासन के पैसे से इन सोलर उपकरणों को लगाए जाने पर रोक लगा दी गई है।

पौने दो साल पहले लिया था निर्णय- प्रदेश सरकार ने करीब पौने दो साल पहले 9 सितम्बर 2024 को यह फैसला किया था कि स्थानीय निकायों द्वारा जो सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर स्टड, हाईमास्ट लाइट और सोलर ट्री जैसे उपकरण शासन द्वारा दी गई राशि से या सीएसआर फंड से कराए जाते हैं उस राशि का दुरुपयोग होता है। इसकी वजह यह है कि सोलर के ऐसे उपकरण लगाने के बाद इन उपकरणों की सफाई दुर्कर है, जिसके चलते ये कुछ समय के अंतराल के बाद बेकार हो जाते हैं। ऐसे में इसको लगाने में खर्च की गई राशि की उपयोगिता जीरो हो जाती है। इसलिए शासन द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने फैसला लिया कि सोलर लाइट, सोलर ट्री, सोलर हाईमास्ट या अन्य ऐसे उपकरण शासन की ओर से निकायों में नहीं लगाए जाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास, नगरीय विकास और आवास तथा नवीन और नवकरणीय ऊर्जा समेत सभी विभागों को इस निर्णय पर काम करने के लिए कहा गया था। बताया जाता है कि इसको लेकर पहले भी एक बार पत्र लिखा गया था लेकिन जिलों से आई रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायतों और शहरी वार्डों में ये सोलर उपकरण शासन के खर्च से लगवाए जा रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं।

फैसला लेने वाली कमेटी में शामिल हैं ये अफसर

राज्य स्तरीय समन्वय समिति की जिस बैठक में यह फैसला किया गया है, उसमें मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास, प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम, अध्यक्ष एमपी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी शामिल हैं।

सीहोर में खरीदे प्लांट, 14 साल बाद भी नहीं हुआ विकास

प्लांट मालिकों की भोपाल के न्यू मार्केट में बैठक, बिल्डर पर कार्रवाई की मांग

भोपाल। सीहोर जिले के ग्राम चांदी स्थित कॉलोनी में कुछ लोगों ने साल 2012 में प्लांट खरीदे थे। प्लांट मालिकों का आरोप है कि ढाल इंफ्राबुल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने 32 सुविधाओं का वादा कर प्लांट बेचे, लेकिन 14 साल बाद भी विकास कार्य नहीं किए गए। इसी मुद्दे पर रविवार भोपाल में प्लांट मालिकों की बैठक हुई। प्लांट मालिकों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने कॉलोनी डेवलपमेंट के नाम पर प्लांट खरीदारों से डेवलपमेंट चार्ज वसूला, लेकिन अभी तक जमीन पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ और केवल कागजी प्रक्रिया ही पूरी की गई है।



मालिकों ने बताया कि वे पहले भी बिल्डर के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और

भोपाल व सीहोर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लंबे समय से

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)



कहते हैं लोगों के सिर पर ई-चालान भूत की तरह मंडराने लगा है। ई-चालान लोगों को सोने भी नहीं दे रहा है। पता नहीं कब, कहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में मोबाइल पर ई-चालान का मैसेज आ जाया। अब तो यह भी भय सताने लगा कि ई-चालान नहीं पटया तो सिपाही घर आकर गाड़ी जब्त न कर लें। ई-चालान पटते-पटते कुछ लोग साइबर ठगी के शिकार हो जा रहे, यह अलम। पुलिस ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने के कारण लोगों को सीधे दंड तो दे रही है, पर अपनी कमी या खामी को देख नहीं रही है। कई सिग्नल्स पर जेब्रा क्रॉसिंग मिट गए हैं। स्टाप लाइन का अता-पता नहीं। सड़कों पर स्पीड लिमिट के बोर्ड नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी लोगों को दंड मिल रहा है। सिद्धांत की बात तो यह है कि पहले हम सुधरे, फिर जग को सुधारने चले। सड़क में पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त हो। पार्किंग की जगह ठेले-खोमचे नजर आ जाते हैं। कई बैंक और संस्थान, यहां तक कि छोटे शॉपिंग सेंटर में चाहत पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम और पुलिस को उस तरफ भी नजरें दौड़ानी चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था

सुधारने और दुर्घटनाएँ रोकने के लिए पुलिस को लोगों को भरोसे में लेना होगा। लोगों को ट्रैफिक रूल की जानकारी देने जगह-जगह कैम्प लगाने होंगे, लोग जागरूक होंगे, तो नियम का पालन करेंगे। ई-चालान टैरर से लोग भयभीत होने के साथ गुस्से में भी हैं। परिवहन संघ ने तो ई-चालान के खिलाफ विरोध दर्ज करा ही दिया है।

वन बल प्रमुख की दौड़ में पांडे और यादव

कहते हैं कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख की दौड़ में 1994 बैच के आईएफएस अरुण पांडे और 1995 बैच के आईएफएस ओमप्रकाश यादव आगे चल रहे हैं। कुछ समय पहले वन बल प्रमुख के लिए 1992 बैच के आईएफएस कौशलेन्द्र कुमार का नाम भी चर्चा में था। अभी अरुण पांडे वन्यप्राणी संरक्षण के मुखिया हैं, जबकि ओपी यादव कैम्पा का काम देखते हैं। माना जा रहा है कि 29 मई के बाद राज्य को नया वन बल प्रमुख मिल जाएगा। वर्तमान वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव मई में रिटायर हो जाएंगे। पहले हल्ला था कि राव साहब को एक साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। कांग्रेस राज में श्रीनिवास राव को कई अफसरों की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर वन बल प्रमुख बनाया गया था और मामला कोर्ट तक गया था। इस कारण श्रीनिवास

मोदी के मन की बात से आमजन को मिलती है नई दिशा

कहा-पीएम ने मन की बात को बिठा दिया है देशवासियों के मन में



ही अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान, यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। हमारे साथी पहले भी इस तरह की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। इस बार जनगणना का उनका अनुभव, अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर-घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे नागरिकों से बात करके उसी में सारी जानकारी दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है, नागरिकगण खुद भी अपनी

जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले सबके लिए यह सुविधा शुरू होगी। नागरिक अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब जब नागरिक यह प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो उन्हें एक विशेष आईडी मिलती है। ये आईडी उनके मोबाइल या ई-मेल आईडी पर आती है। बाद में जब कर्मचारी उनके घर आता है, तो वे यही आईडी दिखाकर अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इससे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश के जिन राज्यों में स्व-गणना का काम पूरा हो गया है, वहां,

गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया की अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। देश की जनगणना सिर्फ एक शासकीय काम नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है। नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है और इसे पूरी डिजिटल सुरक्षा के साथ सुरक्षित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि आइए, हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें और जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

भोपाल के अन्ना नगर में कचरा प्लांट में भीषण आग

25 टन कचरा जला; 8 घंटे से 11 फायर स्टेशन की गाड़ियां काबू करने में जुटी

भोपाल। भोपाल के अन्ना नगर स्थित गाबेज ट्रांसफर स्टेशन में शनिवार देर रात आग लग गई। आग इतनी भीषण है कि 8 घंटे बाद भी काबू में नहीं आई है। 11 फायर स्टेशन से 50 से ज्यादा दमकल-टैंकर पानी अब तक डाला जा चुका है। आग में यहां रखा 25 टन कचरा जलकर राख हो गया है। अन्ना नगर में यह कचरा प्लांट मुख्य रोड से 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। इस वजह से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। सड़क किनारे रहने वाले लोग रातभर नहीं सोए। रात में ही निगम अफसर मौके पर पहुंचे। वहीं, हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। सभी स्टेशनों से दमकलें मौके पर पहुंची गईं। फतेहपुरा, फतेहगढ़, बैरागढ़, कोला, गांधीनगर समेत सभी 11 फायर स्टेशनों से दमकलें मौके पर भेजी गईं। शनिवार रात करीब 12 बजे आग लगी थी, जो रविवार सुबह 8 बजे तक भी काबू में नहीं आई है। अभी भी काफी हिस्से में आग भभक



रही है। कपड़ों की वजह से काबू में नहीं आग जानकारी के अनुसार, इस गाबेज ट्रांसफर स्टेशन में रिसेलिंग वाला कपड़ों का ढेर लगा था। यह करीब 150 टन था। वहीं, 25 टन कचरा भी था। रिसाइलिंग यूनिट में सबसे पहले आग लगी थी, जो करीब एक महीने से बंद पड़ा था। हालांकि, आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो सका है।

राजधानी भोपाल में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद

इंदौर-ग्वालियर-उज्जैन में भी सुट्टी, 22 जिलों में लू का अलर्ट, 3 दिन बारिश के आसार

भोपाल। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में पारा चढ़ा हुआ है, जबकि मालवा-निमाड़ यानी, इंदौर-उज्जैन के साथ भोपाल, नर्मदापुरम में भी सूरज के तीखे तेवर हैं। शनिवार को 6 शहरों में पारा 44 डिग्री या इससे अधिक पहुंच गया। खजुराहो प्रदेश में सबसे ज्यादा 44.6 डिग्री रहा। रविवार को ग्वालियर समेत 22 जिलों में हीट वेव यानी, लू का अलर्ट है। दूसरी ओर, 27 अप्रैल से 3 दिन तक प्रदेश में गरज-चमक और बारिश होने के आसार है। रविवार को जिन जिलों में लू की चेतावनी है, उनमें ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाण्डुरा, रायसेन, नर्मदापुरम, नीमच, मंडसौर, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर शामिल हैं। भोपाल, इंदौर-उज्जैन में भी गर्मी का असर बना रहेगा। यहां पारा 41 डिग्री के पार ही

रहेगा। वहीं, बढ़ती गर्मी को देखते हुए भोपाल में 8वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इंदौर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों और 8वीं तक के सभी स्कूलों में 27 से 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया गया है। यहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे



खजुराहो सबसे गर्म, ग्वालियर-उज्जैन में 43 डिग्री पहुंचा तापमान

इससे पहले शनिवार को आसमान से जैसे आग बरसी। 6 शहरों में पारा 44 डिग्री या इससे अधिक पहुंच गया। छतरपुर जिले का खजुराहो सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, खजुराहो के बाद रतलाम में पारा 44.5 डिग्री दर्ज किया गया। दतिया-धार में 44.1 डिग्री, नागाव-श्योपुर में 44 डिग्री, टीकमगढ़-मंडला में 43.8 डिग्री, दमोह में 43.6 डिग्री, उमरिया में 43.5 डिग्री, नर्मदापुरम में 43.4 डिग्री, गुना-सतना में 43.3 डिग्री, सीधी में 43.2 डिग्री, सागर में 43.1 डिग्री, रीवा-मलनाखंड में 43 डिग्री, रायसेन में 42.8 डिग्री, खरगोन में 42.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, बड़े शहरों में ग्वालियर-उज्जैन में पारा 43 डिग्री पहुंच गया। भोपाल में 42.4 डिग्री, इंदौर में 42.2 डिग्री और जबलपुर में तापमान 42.6 डिग्री रहा।

लोगों की नींद हराम कर दी है ई-चालान ने

राव के एक्सटेंशन की संभावना कम बताई जा रही है। श्रीनिवास राव के अलावा जून में तपेश कुमार झा और जुरलाई में अनिल साहू भी रिटायर होने वाले हैं। इनके अलावा दो सीसीएफ भी अगले कुछ महीने में रिटायर होने वाले हैं। कहा जा रहा है वन विभाग में मई के बाद बड़े फेरबदल होंगे।

अफसरों की कर्मठता

कहते हैं पटन-पाटन वाले विभाग में अफसरों की कर्मठता चर्चा में है। वैसे तो सरकारी कामकाज का समय सुबह 10 बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रहता है। लेकिन इस विभाग के अफसर और कर्मचारी रात को भी काम करने से परहेज नहीं करते हैं, खासतौर से टैंडर के मामले में। चर्चा है कि विभाग के अफसरों ने एक टैंडर आधी रात खोल लिया। टैंडर फर्नीचर सप्लाय से जुड़ा बताया जा रहा है। अब आजकल ऑनलाइन है। सबकुछ पर कड़ियों की निगाहें लगी रहती है। ऐसे लोगों ने कुछ जानकारियां भी निकाल ली और विभाग की पोल-पट्टी खोलनी शुरू कर दी है। अब देखिये क्या होता है।

मंत्री के ओएसडी का कारनामा

कहते हैं एक मंत्री के ओएसडी अपने एक रिश्तेदार को अपने विभाग से जुड़े संस्थान में बैंक डोर इट्री

कराना चाहते थे। मामला फिट बैठ भी गया था, पर कुछ लोगों की निगाह पड़ गई और दाना-पानी लेकर इट्री के खिलाफ पड़ गए। इसके बाद ओएसडी का अभियान सफल नहीं हो पाया। ओएसडी के पास दोहरा चार्ज है। मंत्री के दफ्तर में कुछ समय गुजारने के बाद वे एक बड़े संस्थान के मुखिया की भूमिका भी निभाते हैं। अब मंत्री जी और संस्थान के कर्ताधर्ता की मेहरबानी हो तो फिर ओएसडी साहब के पर लगेगे ही और जो चाहे मनमर्जी करेंगे।

चर्चा में जिम

राजधानी रायपुर में आजकल एक जिम चर्चा में है। इस जिम याने व्यायामशाला में नामी-गिरामी लोग जाते हैं। नेता-अफसर सभी। यह जिम स्टेट्स सिम्बल भी बन गया है। इस जिम में जाते वक्त एक महिला अफसर लिफ्ट में फंस गईं, तब से यह जिम सुर्खियों में है। इसके पहले भी कई लोग लिफ्ट में फंस चुके हैं, पर इस जिम में एक रिटायर आईएएस की हिस्सेदारी से सबके मुँह सिल गए। रिटायर आईएएस को जमीन किंग भी कहा जाता है। ये पद में रहते एक क्लब में हिस्सेदार हो गए थे। जब क्लब में बवाल हुआ, तब मामला सामने आया। अबकी बार लिफ्ट कांड होने के बाद सारी चीजें उजागर होनी शुरू हुई है।

मुख्यमंत्री ने आमजनों से किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर मौजूद आमजनों विशेषकर युवाओं से आत्मीय संवाद किया। उनके साथ स्वल्पाहार कर नारी शक्ति वंदन सहित विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों की शिक्षा की पुष्टा व्यवस्था एवं प्रोत्साहन सहयता, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण, इनकी आजीविका, समान वेतन और इन्हें स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन पर केंद्र सरकार तत्पर होकर प्रयास कर रही है, पर विपक्षी दलों के असहयोग के कारण यह प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाया।

सीएम ने बच्चों का बढ़ाया हौसला

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रेस्टोरेंट में कैप पेंटिंग कर रहे चार छोटे बच्चों से बाल सुलभ वातालाप कर उनकी हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने बच्चों को अपने हाथों से नाश्ता कराया। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई सम्बंधित बातचीत कर उन्हें हमेशा अपने बड़े-बुजुर्गों, माता-पिता और बड़े भाई-बहनों का सम्मान करने और माता-पिता के नाम का उच्चारण करते समय सदैव 'श्रीमती' और 'श्री' से प्रारंभ कर सम्मानजनक संबोधन ही करने की सीख दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आमजनों, युवाओं और बच्चों के साथ सहज रूप से अभिभावक की तरह अनौपचारिक चर्चा की और सबके साथ समूह चित्र खिंचवाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मन की बात के श्रवण एवं आमजन से संवाद कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, श्री राहुल कोठारी, श्री रविन्द्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिकगण उपस्थित थे।

सीएम ने कहा-जल संरक्षण में हम हैं अबल

कार्यक्रम के बाद मॉडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'मन की बात' प्रधानमंत्री श्री मोदी का पूरे देश को एकजुटता का सकारात्मक संदेश देने का अद्भुत प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारा मध्यप्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तहत हमारी सरकार नई जल संरचनाओं के निर्माण-विस्तार के साथ-साथ पुराने कुओं, तालाबों, बावड़ियों और अन्य पारम्परिक जल स्रोतों जैसे हैंडपंप आदि को भी नया जीवन देने का प्रयास कर रही है। इस अभियान में जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। यह अभियान 30 जून तक अनवरत चलेगा।